केवल आप के लिये
गांव–गांव शहर–शहर देश दुनियां में अपनों तक पहुंचाना है तो भारतीय बस्ती दैनिक वेब www.bhartiyabasti.com और उसका छपा संस्करण सबसे बेहतर माध्यम
सम्पर्क-bhartiyabasti@gmail.com
मो0 9450567450| 9336715406

दैनिक
भारतीय बस्ती

भारतीय बस्ती
www.bhartiyabasti.com
के लिये विज्ञापन बुक कराये।
विचार, प्रचार का सशक्त माध्यम
सम्पर्क
मो0 9336715406
8400925463
भारतीय बस्ती आमंत्रण मूल्य 2रूपया

R.N.I. 38784/81 डाक पंजीकरण सं0 B.S.T 59 बस्ती, वर्ष :49 अंक 127 रविवार 29 नवम्बर 2026 (बस्ती संस्करण) बस्ती एवं अयोध्या–फैजाबाद से एक साथ प्रकाशित पृष्ठ :4मूल्य:3.00 रुपया www.bhartiyabasti.com

एक नजर

रूधौली गन्ना मिल में पेराई शुरू



–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती । बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड रूधौली के नवीन पेराई सत्र का शुभारंभ शनिवार को वैदिक मंत्रोच्चारण और विधि–विधान से हवन–पूजन के साथ किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में गोविंद नगर गन्ना विकास समिति के अध्यक्ष पुष्कर आदित्य सिंह, बस्ती गन्ना विकास समिति के अध्यक्ष प्रदीप कुमार सिंह 'पिंकू', डुमरियागंज की विधायिका सायदा खातून, रूधौली ब्लॉक प्रमुख आलोक चौधरी तथा रामनगर ब्लॉक प्रमुख यशकांत सिंह मौजूद रहे। मिल प्रशासन की ओर से इकाई प्रमुख डॉ. जेपी त्रिपाठी, महाप्रबंधक (गन्ना) लवकुश सिंह चौहान, इंजीनियरिंग हेड श्रवण सिंह और उपमहाप्रबंधक अनिल कुमार शुक्ला ने आए हुए अतिथियों का स्वागत किया। स्वागत की अगुवाई सीनियर गन्ना अधिकारी बाल सिंधु पांडे, क्षेत्रीय अधिकारी प्रवीण सिंह और श्याम नारायण सिंह ने की। इस अवसर पर भारी मात्रा में किसान भी उपस्थित हुए।

पेराई सत्र की शुरुआत के अवसर पर मिल परिसर में सबसे पहले गन्ना लदी बैलगाड़ी, ट्रॉली और ट्रक का पारंपरिक पूजन किया गया। इसके उपरांत डोंगे में गन्ना डालकर पेराई कार्य का विधिवत प्रारंभ हुआ और सभी उपस्थित लोगों के बीच मिष्ठान वितरण किया गया। इस दौरान बैलगाड़ी लेकर आए कृषक को डुमरियागंज की विधायिका सायदा खातून ने अंगवस्त्र और मिठाई भेंट कर सम्मानित किया व शुभकामनाएं दीं। वहीं, ट्रॉली पर गन्ना लेकर पहुंचे किसान का गोविंद नगर गन्ना विकास समिति के अध्यक्ष पुष्कर आदित्य सिंह ने अंगवस्त्र एवं मिठाई प्रदान कर स्वागत किया तथा ट्रक पर गन्ना लेकर आए किसान का स्वागत बस्ती गन्ना विकास समिति के अध्यक्ष प्रदीप कुमार सिंह रुपिकूर ने किया। कार्यक्रम के दौरान किसानों की सुविधा और जलपान के लिए मिल परिसर में विशेष स्टॉल भी लगाए गए, जहां कृषकों ने जलपान किया।

इस अवसर पर यूनिट हेड डॉ. जेपी त्रिपाठी ने कहा कि मिल प्रबंधन किसानों के हितों के प्रति पूरी तरह समर्पित है। पेराई सत्र को सुचारु रूप से चलाने के लिए सभी तकनीकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होने दी जाएगी।

सीनियर गन्ना अधिकारी बाल सिंधु पांडे ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि वे मिल को साफ–सुथरा, ताजा और जड़–पत्ती रहित गन्ना ही आपूर्ति करें। उन्होंने भरोसा दिलाया कि गन्ना पर्ची वितरण और तौल की प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी रखा गया है।

वहीं, जोनल एचआर प्रमुख एनके शुक्ला ने कार्यक्रम में आए जनप्रतिनिधियों, समिति के पदाधिकारियों और क्षेत्रीय किसानों का आभार व्यक्त किया।

फंदे से लटका मिला युवक का शव

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती । दुबौलिया थाना क्षेत्र में चिलमा बाजार के पास बरदिया में शनिवार सुबह 7 बजे एक युवक का शव किराये के कमरे में फंदे से लटका मिला। परिजन उसे जगाने पहुंचे थे, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। खिड़की से देखने पर शव दिखाई दिया। मृतक की पहचान शिवम पटवा (24), पुत्र बेचू लाल पटवा के रूप में हुई है। वह पांच भाई–बहनों में तीसरे नंबर पर थे और भाइयों में सबसे बड़े थे। शिवम जयमाल डेकोरेशन का काम करते थे। वह बरदिया में गोकुल प्रजापति के मकान में किराये पर रहते थे। परिजनों के मुताबिक, शिवम रात में खाना खाने के बाद कमरे में सोने चले गए थे। सुबह करीब 7 बजे परिवार के लोग मकान पर पहुंचे और दरवाजा खुलवाने की कोशिश की। दुबौलिया थानाध्यक्ष आलोक कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है।

परिसीमन के बाद पीओके की बारी

नई दिल्ली (आभा)। केंद्र सरकार के नए परिसीमन विधेयक के मसौदे में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) का स्पष्ट उल्लेख कर बड़ा संदेश दिया है। 30 नवंबर को लोकसभा में पेश किए जाने वाले इस विधेयक में प्रावधान किया गया है कि जैसे ही पाकिस्तान का अवैध कब्जा समाप्त होगा कि भारत का चुनाव आयोग पीओके के अंतर्गत आने वाले जम्मू–कश्मीर विधानसभा क्षेत्रों के लिए



परिसीमन आयोग के रूप में कार्य करेगा। बता दें कि अभी तक इसका ड्राफ्ट सार्वजनिक नहीं किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस विधेयक के साथ–साथ 132वें संविधान संशोधन विधेयक, 2026 और केंद्र शासित प्रदेश संशोधन विधेयक, 2026 को भी मंजूरी प्रदान की गई।

परिसीमन का मुख्य उद्देश्य जनसंख्या के बदलते आंकड़ों के अनुरूप प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं का समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना होता है। संविधान के अनुच्छेद 82 के तहत संसद प्रत्येक जनगणना के बाद एक परिसीमन अधिनियम लागू करती है, जिसके आधार पर एक स्वतंत्र परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है।

जम्मू–कश्मीर को लेकर परिसीमन का इतिहास काफी अलग रहा है। अनुच्छेद 370 के निरस्त होने और जम्मू–कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के लागू होने से पहले राज्य की विधानसभा सीटों का परिसीमन जम्मू–कश्मीर के अपने संविधान और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत होता था। पुनर्गठन के बाद केंद्र सरकार ने मार्च 2020 में न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में परिसीमन आयोग का गठन किया था। इस आयोग ने मई 2022 में अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपी, जिसके बाद जम्मू–कश्मीर विधानसभा की सीटों की संख्या 83 से बढ़कर 90 हो गई। जम्मू क्षेत्र में 43 और कश्मीर घाटी में 47 सीटें।

पशुपतिनाथ से लौटी श्री गंगा कलश यात्रा का हुआ भव्य स्वागत

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। भारत और नेपाल की साझा धार्मिक, आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत को जोड़ने वाली श्री गंगा कलश यात्रा के शनिवार को हर्रैया विकासखंड के तिनौता गांव पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। नेपाल के काठमांडू स्थित प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर में गंगाजल से भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के बाद वापस लौटी यात्रा का वरिष्ठ समाजसेवी लक्ष्मीकांत ओझा के नेतृत्व में ग्रामीणों ने पुष्पवर्षा कर आत्मीय अभिनंदन किया। इस दौरान पूरा वातावरण श्रद्धा और भक्ति के भाव से सराबोर रहा।

स्वागत समारोह को संबोधित करते हुए वरिष्ठ समाजसेवी लक्ष्मीकांत ओझा ने कहा कि मां गंगा केवल भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म की पहचान नहीं हैं, बल्कि भारत और



नेपाल की अटूट आध्यात्मिक एकता की भी प्रतीक हैं। पशुपतिनाथ मंदिर में गंगाजल से जलाभिषेक की परंपरा दोनों देशों के बीच सदियों पुराने धार्मिक, सांस्कृतिक और आत्मीय संबंधों को और मजबूत करती है। गंगाजल की यह अविरल धारा दोनों देशों के बीच मैत्री, प्रेम और सद्भाव का संदेश दे रही है। यात्रा का नेतृत्व कर रहे गंगोत्री धाम के रावल शिवप्रकाश महाराज ने बताया कि प्रतिवर्ष गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने के बाद 1100 लीटर से अधिक क्षमता वाले दिव्य कलश में पवित्र गंगाजल भरकर नेपाल की राजधानी काठमांडू स्थित पशुपतिनाथ मंदिर पहुंचाया जाता है। इसी पवित्र जल से वर्षभर भगवान पशुपतिनाथ का जलाभिषेक किया जाता है। यह परंपरा भारत और नेपाल की धार्मिक एकात्मता का अनुपम उदाहरण है।

इस अवसर पर राम समुझ ओझा, राम प्रसाद ओझा, अम्बिका प्रसाद ओझा, उमाकांत तिवारी, विदेश्वरी ओझा, विनोद ओझा, जगदंबा प्रसाद ओझा, कृपाशंकर ओझा, प्रेम शंकर ओझा, सुभाष चंद्र, शिव शंकर शुक्ल, रमेश चौहान, वाल्मीक ओझा, देवांश, आयांश सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।

पदोन्नति में देरी के विरोध में शिक्षकों का अनशन तीसरे दिन भी जारी

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती । शिक्षकों की पदोन्नति में देरी के विरोध में उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ का जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर धरना शनिवार को तीसरे दिन भी जारी रहा। शिक्षक पदोन्नति आदेश जारी करने और काउंसिलिंग जनपद स्तर पर कराने की मांग कर रहे हैं। संगठन ने कहा है कि मांगें पूरी होने तक धरना और आंदोलन जारी रहेगा।

आन्दोलन के तीसरे दिन कृष्ण बहादुर पाल, अखिलेश तिवारी, विजय प्रकाश, श्याम नरायन मिश्र, विपिन शुक्ल अनशन पर बैठे।

संघ जिलाध्यक्ष उदय शंकर शुक्ल के नेतृत्व में शिक्षक पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर पदोन्नति प्रक्रिया तेज करने की मांग किया था। कहा कि शिक्षकों के संघर्ष का ही परिणाम है कि सरकार ने इसे गंभीरता से लिया और पदोन्नति प्रक्रिया में मनमानी एवं अवैध वसूली से जुड़े जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का फैजाबाद स्थानान्तरण हो गया। कहा कि नवागत बीएसए से मांग होगी कि काउंसिलिंग कराकर अति शीघ्र पदोन्नति आदेश जारी कर दिया जाय। कहा कि सोमवार को भी अनशन जारी रहेगा।



–शिक्षकों की एकजुटता से हुआ बीएसए का तबादला– उदयशंकर शुक्ल

संघ जिलाध्यक्ष उदय शंकर शुक्ल ने कहा कि गत 6 नवम्बर को बीएसए कार्यालय पर धरना–प्रदर्शन के दौरान अधिकारियों ने 20 नवंबर से पहले पदोन्नति आदेश जारी करने का आश्वासन दिया था। इसके बाद शिक्षकों की अंतिम वरिष्ठता सूची जारी हुई, लेकिन पदोन्नति आदेश अब तक जारी नहीं हुआ।

शिक्षक संघ ने 16 नवंबर को जारी उस आदेश पर भी आपत्ति जताई है, जिसमें सभी विकास क्षेत्रों में 23 और 25 नवंबर को काउंसिलिंग कराने का निर्देश दिया गया था। 20 नवंबर तक पदोन्नति का मिला था आश्वासन लेकिन आदेश न आने पर शिक्षक फिर धरने पर बैठे। संगठन का कहना है कि विकासखंड स्तर पर काउंसिलिंग कराने से प्रक्रिया में देरी हो रही है। संघ के मुताबिक, प्रदेश के कई जिलों में जनपद स्तर पर काउंसिलिंग कराकर पदोन्नति आदेश जारी किए जा चुके हैं।

अनशन और आन्दोलन के दौरान वरिष्ठ उपाध्यक्ष आनन्द दूबे, जिला मंत्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह, जिला संयुक्त मंत्री राजकुमार सिंह, जिला कोषाध्यक्ष अभय सिंह यादव, सदर अध्यक्ष शैल कुमार शुक्ला, रीता शुक्ला, प्रदीप मिश्रा, रजनीश मिश्र, सन्तोष कुमार शुक्ल, कन्हैयालाल भारती, अभिषेक उपाध्याय, इन्दुबाला त्रिपाठी, रक्षाराम वर्मा, नरेन्द्र कुमार द्विवेदी, सतीश शंकर शुक्ल, ओम प्रकाश पाण्डेय, राजीव पाण्डेय आदि ने सम्बोधित करते हुये कहा कि पदोन्नति आदेश को तत्काल जारी कराया जाय। संचालन कैलाशनाथ ने किया।

यह जानकारी देते हुये संघ के जिला प्रवक्ता सूर्यप्रकाश शुक्ल ने बताया कि बीएसए कार्यालय के समक्ष तीसरे दिन जारी आन्दोलन के दौरान मुख्य रूप से प्रणव मिश्र, अमरेश कुमार द्विवेदी, लवकुश त्रिपाठी, अमित कुमार पाण्डेय, रामलखन दूबे, राम औतार, चन्दन कुमार, ओम प्रकाश, ज्ञानेश्वर शुक्ल, अरविन्द कुमार पाण्डेय, रविन्द्रनाथ, सुनील कुमार पाण्डेय, रामचन्द्र गुप्त, सुनील कुमार तिवारी,संध्या त्रिपाठी, अफशा परवीन, शिवम शुक्ल, स्कन्द कुमार मिश्र, श्वेता चौधरी, गीता गौतम, अभिराम वर्मा, राजकुमार पाण्डेय, वृजमोहन कन्नौजिया, गौरव त्रिपाठी, वैभव कन्नौजिया, राम मोहन उपाध्याय, लालेन्द्र कन्नौजिया, विनोद कुमार यादव, दिनेश कुमार, मित्र प्रकाश शुक्ल, अशोक कुमार मिश्र, गिरजेश उपाध्याय, दुर्गा प्रसाद उपाध्याय, अनूप सिंह, आभाकान्त द्विवेदी, अतुल पाण्डेय सहित अनेक शिक्षक शामिल रहे।

कांग्रेस की 'वोट बचाओ, देश बचाओ' चौपाल में अभिषेक दत्त ने भाजपा सरकार पर साधा निशाना

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। शनिवार को महान सन्त ज्योतिबा फुले की पुण्य तिथि के दिन महादेवा विधानसभा क्षेत्र के बनकटी ब्लॉक अंतर्गत रौतापार चौराहे पर कांग्रेस पार्टी द्वारा 'वोट बचाओ, देश बचाओ' चौपाल का आयोजन पूर्व महादेवा विधानसभा प्रत्याशी बृजेश कुमार आर्य के नेतृत्व में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव अभिषेक दत्त रहे। चौपाल में कांग्रेस नेताओं ने मतदाता अधिकारों की रक्षा, लोकतंत्र की मजबूती और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी बात रखी।

चौपाल को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि अभिषेक दत्त ने कहा कि सभी लोगों को इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि किसी भी पात्र मतदाता का वोट न कटने पाए। उन्होंने लोगों से अपने मताधिकार के प्रति जागरूक रहने और आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने की अपील की, ताकि जनता के हक और अधिकारों की रक्षा हो सके।

विशिष्ट अतिथि कांग्रेस



–बृजेश आर्य के नेतृत्व में आयोजित चौपाल में वोटर अधिकारों की रक्षा और विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस नेताओं ने भरी हुंकार

जिलाध्यक्ष विश्वनाथ चौधरी ने कहा कि पहले मतदाता यह तय करते थे कि सरकार किसकी बनेगी, लेकिन अब ऐसी स्थिति पैदा हो रही है कि सरकार यह तय करने का प्रयास कर रही है कि वोट कौन देगा। उन्होंने इसे लोकतंत्र के लिए गलत बताते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी किसी का हक और अधिकार छिनने नहीं देगी। उन्होंने भाजपा पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए कहा कि लोकतंत्र में जनता के अधिकार सर्वोपरि हैं। पूर्व महादेवा विधानसभा प्रत्याशी एवं कार्यक्रम के आयोजक बृजेश कुमार आर्य ने कहा कि सभी लोग अपने मताधिकार के प्रति सजग रहें और यह सुनिश्चित करें कि किसी भी पात्र व्यक्ति का वोट न कटे। उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने की अपील करते हुए कहा कि यदि किसी भी व्यक्ति को वोट या अन्य अधिकारों से संबंधित कोई समस्या आती है तो कांग्रेस पार्टी उनके साथ मजबूती से खड़ी रहेगी। कार्यक्रम में पूर्व विधायक अंबिका सिंह, देवेन्द्र श्रीवास्तव, डॉ. आलोक रंजन वर्मा, अनिल कुमार भारती, अमर बहादुर शुक्ला, मनीष दुबे, अंकित कुमार, फजले आजम, दुर्गेश चौधरी, संजय चौधरी, रामप्रीत, शोभित चौधरी, प्रबंधक जीपी शर्मा, अमीर सिद्दीकी, नागेंद्र कुमार, अल्ताफ, माजिद, साजिद, विश्वजीत चौधरी, बजरंगी मिश्रा, प्रवीण चौधरी, चंद्रेश कुमार, सर्वेश शुक्ला, शुभम गौड़, त्रिभुवन चौधरी, दिवाकर चौधरी, देवेंद्र शुक्ला, सोनू मिश्रा, दुधनाथ पटेल, शुभम गांधी, राम गोपाल, दिनेश, रामचरण चौधरी, अनिल चौधरी, राजेश चौधरी, अंकित पांडे, उमेश उपाध्याय, द्वारिका शुक्ला सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता आदि उपस्थित रहे।

वोट चोरी को छिपाने के लिए परिसीमन–राहुल गांधी

नई दिल्ली (आभा)। राहुल गांधी ने शनिवार को परिसीमन बिल पर भाजपा पर निशाना साधा और दावा किया कि हमने उन्हें घेर लिया है। भाजपा वोट चोरी को छिपाने के लिए परिसीमन करवा रही है। हम भाजपा को कामयाब नहीं होने देंगे। राहुल गांधी ने एक बार फिर से दोहराया कि 2024 का लोकसभा चुनाव अवैध था। गांधी ने आरोप लगाया कि भाजपा देश को तानाशाही की ओर धकेल रही है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया, हम ऐसा नहीं होने देंगे।

राहुल गांधी ने आगे कहा, 'कास्ट सेंसस को किनारे कर दिया गया है और 2027 की सेंसस को बेमतलब



कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ बहुत ही मुश्किल फैक्ट्स सामने आएंगे, जो भाजपा को पसंद नहीं हैं। इसलिए वे 2011 की सेंसस का इस्तेमाल करने जा रहे हैं और 2051 तक सब कुछ फ्रीज कर दिया जाएगा। मतलब 40 साल तक, आप सोशल जस्टिस को भूल सकते हैं। एससीएसटी, ओबीसी के अधिकारों को कमजोर कर रहे हैं, माइनॉरिटीज को कमजोर कर रहे हैं। एससी, एसटी सीटों का हिस्सा 40 साल तक फ्रीज रहेगा। नेता विपक्ष ने आगे कहा कि उनकी आबादी बढ़ने वाली है फिर भी उनकी सीटें नहीं बढ़ेंगी। जाहिर है, वे कास्ट सेंसस का नतीजा नहीं चाहते हैं। हम एक बायपार्टिसन डिलिमिटेशन कमीशन चाहते हैं। महिलाओं का रिजर्वेशन 850 पर, और हम कहते हैं कि ओबीसी के लिए सब–कोटा के साथ 543 पर। यहां सवाल भाजपा को भारतीय लोकतंत्र की नींव को फिर से बनाने के लिए एक खाली स्लेट देना है।

सोनहा–शिवघाट मार्ग के निर्माण में देरी और गुणवत्ता को लेकर पूर्व विधायक संजय प्रताप जायसवाल ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र

–जांच अधिकारी अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लो.नि.वि. पर मनगढन्त आख्या देने का आरोप

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक संजय प्रताप जायसवाल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर जनपद के सोनहा–शिवघाट मार्ग के निर्माण कार्य में हो रही देरी, निर्माण की गुणवत्ता और निर्धारित मानकों की अनदेखी को लेकर पूरे मामले में प्रभावी कार्रवाई किये जाने की मांग किया है। पत्र में संजय प्रताप ने कहा है कि मामले की जांच का आदेश दिया गया था किन्तु जांच अधिकारी अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लो.नि.वि. बस्ती द्वारा मामले में गलत मनगढन्त रिपोर्ट लगाकर मुख्यमंत्री सन्दर्भ की आख्या भेज दिया गया। पूर्व विधायक संजय प्रताप जायसवाल ने इस पर गंभीर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुये मामले में निष्पक्ष जांच और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग किया है।

पूर्व विधायक संजय प्रताप जायसवाल ने दूसरे पत्र में कहा है कि सोनहा–शिवघाट मार्ग क्षेत्र की जनता के आवागमन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। निर्माण कार्य में देरी होने से स्थानीय नागरिकों, राहगीरों, व्यापारियों, किसानों और



मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके बावजूद यदि जिम्मेदार अधिकारी जमीनी हकीकत की जांच किए बिना गलत रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं, तो यह बेहद गंभीर विषय है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ अधिकारियों की कार्यशैली से सरकार की छवि धूमिल हो रही है। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश में विकास कार्यों और जनसमस्याओं के त्वरित समाधान को लेकर लगातार निर्देश दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रही है।

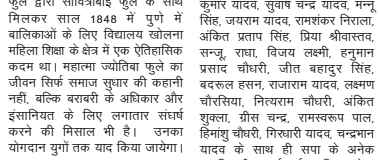
मुख्यमंत्री को भेजे पत्र में पूर्व विधायक ने सोनहा–शिवघाट मार्ग के टेंडर, कार्यादेश, निर्धारित लागत और निर्माण की समयसीमा की जांच कराने, निर्माण सामग्री की गुणवत्ता का परीक्षण मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से कराने तथा संबंधित अधिकारियों और कार्यदायी संस्था की जिम्मेदारी तय करने की मांग की है। साथ ही निर्माण कार्य में अनियमितता मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।

भाजपा नेता पूर्व विधायक संजय प्रताप जायसवाल का कहना है कि उनका उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि जनता को बेहतर सड़क और विकास की सुविधाएं उपलब्ध कराना है। जनता की समस्याओं को उठाना उनका दायित्व है। ऐसे में अधिकारियों को निष्पक्षता के साथ जमीनी स्तर पर जांच करनी चाहिए, न कि गलत रिपोर्ट लगाकर मामले को दबाने का प्रयास करना चाहिए।

ज्योतिबा फुले ने शिक्षा को बदलाव का बड़ा हथियार बनाया– महेन्द्रनाथ यादव

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। शनिवार को समाजवादी पार्टी कार्यालय पर जिलाध्यक्ष और बस्ती सदर विधायक महेन्द्रनाथ यादव की अध्यक्षता में महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले को उनकी पुण्यतिथि पर याद किया गया।



सपा विधायक महेन्द्रनाथ यादव ने कहा कि महात्मा ज्योतिबा फुले ने ऐसे समय में समाज में बदलाव की अलख जगाई थी, जब जातिगत भेदभाव, छुआछूत और महिलाओं को शिक्षा से दूर रखने जैसी कुरीतियां आम थीं। उन्होंने इन सामाजिक बुराइयों का खुलकर विरोध किया और शिक्षा को बदलाव का सबसे बड़ा हथियार बनाया। उनका योगदान सदैव याद किया जायेगा।

पूर्व विधायक राजमणि पाण्डेय, विधायक कविन्द्र चौधरी 'अतुल', समीर चौधरी, मो. श्वालेह, आर.डी. निषाद, संजय गौतम, मो. सलीम, हरेश्याम विश्वकर्मा, बुद्धि प्रकाश आदि ने कहा कि ज्योतिबा फुले द्वारा सावित्रीबाई फुले के साथ मिलकर साल 1848 में पुणे में बालिकाओं के लिए विद्यालय खोलना महिला शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम था। महात्मा ज्योतिबा फुले का जीवन सिर्फ समाज सुधार की कहानी नहीं, बल्कि बराबरी के अधिकार और इंसानियत के लिए लगातार संघर्ष करने की मिसाल भी है। उनका योगदान युगों तक याद किया जायेगा।

महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले को उनकी पुण्यतिथि पर याद करने वालों में मुख्य रूप से अरविन्द सोनकर, अशोक कुमार यादव, सुबाष चन्द्र यादव, मन्नू सिंह, जयराम यादव, रामशंकर निराला, अंकित प्रताप सिंह, प्रिया श्रीवास्तव, सन्जू, राधा, विजय लक्ष्मी, हनुमान प्रसाद चौधरी, जीत बहादुर सिंह, बदरूल हसन, राजाराम यादव, लक्ष्मण चौरसिया, नित्यराम चौधरी, अंकित शुक्ला, ग्रीस चन्द्र, रामस्वरूप पाल, हिमांशु चौधरी, गिरधारी यादव, चन्द्रभान यादव के साथ ही सपा के अनेक पदाधिकारी, कार्यकर्ता शामिल रहे।

कम्बल वितरण कर विधायक अजय सिंह ने जरूरतमंदों को दिया राहत

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। विधानसभा क्षेत्र हर्रैया के पर्सरामपुर ब्लॉक परिसर में आयोजित विशेष श्रमिक सहायता शिविर एवं नव मतदाता जोड़ो अभियान में शनिवार को विधायक अजय सिंह ने सहभागिता करते हुए जरूरतमंदों के बीच कम्बल वितरित किए। इस दौरान उन्होंने उपस्थित माताओं–बहनों एवं क्षेत्रवासियों से आत्मीय संवाद कर उनका कुशलक्षेम जाना और ठंड के मौसम में जरूरतमंदों को राहत पहुंचाई।

विधायक ने कहा कि जनता की सेवा करना और उनके सुख–दुःख में सहभागी बनना एक जनप्रतिनिधि का नैतिक दायित्व है। हर्रैया की जनता का स्नेह और विश्वास ही उनकी सबसे बड़ी पूंजी है। समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक सहायता पहुंचाना और पात्र लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने दिव्यांगों एवं क्षेत्रवासियों से विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के तहत फॉर्म–6 भरकर पात्र नए



मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में जुड़वाने की अपील की। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए प्रत्येक पात्र नागरिक का मतदाता सूची में शामिल होना जरूरी है। साथ ही श्रमिकों से सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए अपना पंजीकरण कराने का आह्वान किया। विधायक ने कहा कि हर्रैया का कोई भी परिवार खुद को अकेला न समझे। जरूरतमंदों की सहायता, श्रमिकों का सम्मान और क्षेत्र का सर्वांगीण विकास उनके सार्वजनिक जीवन का मूल उद्देश्य है। जनसेवा के संकल्प के साथ वह सदैव क्षेत्रवासियों के बीच उपलब्ध रहेंगे।

कार्यक्रम में उप श्रमायुक्त सचिन सिंह, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि पर्सरामपुर शिरीष पाण्डेय, खंड विकास अधिकारी राजेश तिवारी, पूर्व प्रधान राजदत्त शुक्ला, पूर्व प्रधान संघ अध्यक्ष श्रवण कुमार तिवारी, मंडल महामंत्री उदय नारायण पाण्डेय, प्रधान आशीष गुप्ता, शांतिभूषण पाण्डेय, विनोद गुप्ता, देव दीपक पाण्डेय, अखिलेश सिंह, अरविन्द सिंह, बिक्कू सिंह, बड़े सिंह, सूरज पाण्डेय, अवनीश सिंह, आलोक सिंह, पप्पू मौर्य, वीरू सिंह, शैलेश, संदीप, प्रिंस, लवकुश वर्मा सहित हजारों की संख्या में माताएं–बहनें एवं क्षेत्रवासी उपस्थित रहे।

"मुझे अखबार निकालने दो तो मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि कौन धर्म का नियामक है और कौन कानून का निर्माता"—वेंडेल फिलिप्स

दैनिक
भारतीय बस्ती
बस्ती 29 नवम्बर 2026 रविवार

सम्पादकीय

बदलता खान–पान और बीमारी

भारत तेजी से मधुमेह, मोटापे और उच्च रक्तचाप के मरीजों की राजधानी बन रहा है। घर के स्वास्थ्यवर्धक खाने को तिलांजलि देकर चटपटा खाने का जुनून युवा पीढ़ी ही नहीं, पुरानी पीढ़ियों में भी नजर आ रहा है। दरअसल, चीनी व यूरोपीय शैली के खाद्य पदार्थों में तीखे नमक, चीनी तथा अधिक वसा के इस्तेमाल से चटपटे व्यंजन बनाने का जुनून आज भारतीयों के सिर चढ़कर बोल रहा है। खासकर बच्चे व नयी पीढ़ी के युवा इसके दीवाने हैं। लोक कल्याण का दम भरने वाली सरकारों की जन–स्वास्थ्य के प्रति अनदेखी के चलते जीवन शैली के तमाम रोग पनप रहे हैं। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट को पैकेज्ड खाद्य पदार्थों पर स्पष्ट चेतावनी लेबल लगाने के निर्देश देने पड़े हैं। निस्संदेह, देश मे बढ़ते जन–स्वास्थ्य संकट के बीच कोर्ट की यह सार्थक पहल है। अदालत ने भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी एफएसएसएआई को निर्देश दिया है कि जिन भी उत्पादों में चीनी, नमक और सैचुरेटेड फैट की मात्रा अधिक हो, उन पर अलग से लाल रंग की चेतावनी लगायी जाए। ऐसा करके कोर्ट ने कंपनियों की सुविधा के बजाय उपभोक्ताओं के 'जानने के अधिकार' को प्राथमिकता दी है। लेकिन एक बात तो साफ है कि नियामक संस्था खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण अपने दायित्वों के निर्वहन में नाकाम रही है। यही वजह है कि देश की शीर्ष अदालत को इस मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा है। जन स्वास्थ्य के लिये नुकसानदायक मात्रा में चीनी, नमक व वसा का मुद्दा सार्वजनिक विमर्श में होने के बावजूद एफएसएसएआई कई अलग–अलग प्रस्तावों के बीच उलझा रहा। इसमें स्टार 'रेटिंग सिस्टम' भी शामिल रहा है। जिसको लेकर विषय विशेषज्ञों की राय थी कि 'स्टार रेटिंग सिस्टम' से उपभोक्ताओं को स्वास्थ्य जोखिम के प्रति सचेत करने के बजाय, उनमें चयन को लेकर भ्रम बढ़ सकता है। सही मायने में ऐसे किसी निर्देश में स्पष्टता होनी बेहद जरूरी है।

विडंबना है कि देश में अत्यधिक प्रोसेस्ड यानी अल्ट्रा–प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों की खपत में भारी वृद्धि हुई है। इस तथ्य के बावजूद कि देश आज तमाम गैर–संचारी रोगों की गंभीर चुनौती का सामना कर रहा है। फलतरू भारत में मधुमेह, हाइपरटेंशन और मोटापे से करोड़ों लोग प्रभावित हुए हैं। ये रोग जीवनशैली की विसंगतियों से पैदा हुए हैं। विडंबना है कि सीधे खाने के लिये तैयार खाद्य पदार्थों, मीठे पेय पदार्थों और डिब्बाबंद स्नैक्स के लिये बेहद आक्रामक मार्केटिंग के जरिये बच्चों व युवाओं को लुभाया गया। फलतरू जन–स्वास्थ्य के लिये एक बड़ा खतरा पैदा हो गया है। सुप्रीम कोर्ट का पैकेज्ड खाद्य पदार्थों में लाल चेतावनी चिन्ह लगाने का निर्देश समय की सख्त जरूरत है। इससे कंपनियां छोटे अक्षरों की आड़ में पोषण संबंधी जोखिमों को छिपा नहीं सकतीं। लाल चेतावनी पर उपभोक्ताओं का सीधा ध्यान जाएगा। रोजमर्रा के खान–पान की चीजों को चुनते समय, लोगों को जटिल पोषण तालिकाओं को समझने के लिये किसी विशेष ज्ञान या अतिरिक्त समय की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। वहीं जन–स्वास्थ्य की कीमत पर उद्योग जगत को मुनाफे की अनुमति नहीं दी जा सकती है। एफएसएसएआई को चीनी, नमक और सैचुरेटेड फैट के लिये वैज्ञानिक आधार पर तार्किक सीमाएं तय करनी चाहिए। उसे उद्योग जगत की तरफ से आने वाले किसी भी दबाव का सामना करना चाहिए। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाना जरूरी है कि निर्धारित नियमों का सख्ती से पालन किया जाए। इसके अलावा निर्माताओं को छूट का फायदा उठाने, चेतावनियों को कमजोर करने या हानिकारक तत्वों की जगह वैकल्पिक संदिग्ध पदार्थों के इस्तेमाल की किसी भी सूरत में अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। खासकर बच्चों को लुभाने के लिये दिए जाने वाले विज्ञापनों में किए जाने वाले दावों की बारीकी से जांच होनी चाहिए। वास्तव में चेतावनी वाले लेबल उपभोक्ताओं को सही जानकारी देने के साथ ही खाद्य पदार्थों के चयन करने में मददगार हो सकते हैं। देश में हर व्यक्ति को यह जानने का अधिकार है कि उसके खाद्य पदार्थ में क्या–क्या मिलाया गया है। ये व्यक्ति के स्वास्थ्य अधिकार का ही हिस्सा है। जरूरी है कि पैकेट पर मौजूद लाल चेतावनी, कंपनियों की गैर–जिम्मेदाराना हरकतों के लिए एक लक्ष्मण रेखा का काम करे।

भारत– अमेरिका व्यापार समझौता

भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर बातचीत अभी किसी ठोस निष्कर्ष तक नहीं पहुंच सकी है। मगर इस बीच अमेरिका के रुख में जितने उतार–चढ़ाव देखे गए हैं, उससे यही लगता है कि उसकी दिलचस्पी जितनी समझौते को अंतिम शक्ल देने में है, उससे ज्यादा वह अलग–अलग बहानों से मनमानी शर्तें थोपने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में कोई कारण नहीं है कि दोनों देशों के बीच व्यापार वार्ता में परस्पर समान हितों और सम्मान के सवाल को दरकिनार करते हुए समझौते को अंतिम रूप देने में अड़चन लगाई जाए। यह छिपा नहीं है कि जब से भारत और अमेरिका में इस संदर्भ में बातचीत की शुरुआत हुई है, तब से कभी अतिरिक्त शुल्क लगा कर, तो कभी नई शर्तों की घोषणा कर अमेरिका समझौते को अपनी सुविधा का स्वरूप देना चाहता है।

जाहिर है, यह भारत के लिए एक सहज स्वीकार्य स्थिति नहीं है। सवाल है कि क्या अमेरिका को यह ध्यान रखने की जरूरत नहीं महसूस होती कि अगर वह एक संप्रभु देश के साथ कोई समझौता करना चाहता है, तो उसे उसके समान हितों का भी खयाल रखना होगा! गौरतलब है कि अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय (यूएसटीआर) ने भारत से आयातित वस्तुओं पर पच्चीस फीसद शुल्क लगाने का प्रस्ताव किया है।

अमेरिका की इस घोषणा के दायरे में चीन, वियतनाम, जापान, बांग्लादेश, स्विट्जरलैंड और सिंगापुर और यूरोपीय संघ के सत्ताईस देशों के समूह भी हैं, जिन पर इसी तरह शुल्क लगाने की बात कही गई है। यूएसटीआर ने आरोप लगाया है कि भारत में औद्योगिक क्षमता जरूरत से ज्यादा बढ़ने से अमेरिकी कंपनियों को नुकसान पहुंच सकता है। हालांकि भारत ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा है कि हमारे किसी भी क्षेत्र में संरचनात्मक अतिरिक्त उत्पादन की क्षमता नहीं है। भारत की औद्योगिक विनिर्माण गतिविधियां घरेलू मांग और निर्यात जरूरतों के हिसाब से चल रही हैं। इसके अलावा, किसी भी क्षेत्र में जरूरत से ज्यादा उत्पादन नहीं किया जा रहा है। यह विचित्र है कि अमेरिका एक ओर व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने को लेकर अक्सर प्रतिबद्धता जताता रहता है, वहीं हर थोड़े दिनों में वह कोई ऐसी शर्त सामने रख देता है, जिसे ज्यों का त्यों मान लेना भारत के लिए संभव नहीं है। या फिर अमेरिका इस तरह के नुक्ते निकालने की कोशिश करता है, जिसका कोई आधार नहीं होता। सही है कि भारत के साथ व्यापार समझौता अंतिम रूप से हो जाने के बाद अमेरिका ने पच्चीस फीसद शुल्क को घटा कर सत्रह फीसद किए जाने का भी प्रस्ताव दिया है। लेकिन इस क्रम में हर शर्त अगर अमेरिका ही तय करेगा और उसी पर भारत से सहमत होने की उम्मीद करेगा, तो इस एकतरफा समझौते का हासिल भारत के लिहाज से क्या साबित होगा! विडंबना यह है कि पिछले कुछ वर्षों से अमेरिका ने दुनिया के अलग–अलग देशों पर मनमाने तरीके से शुल्क लगाने को अपने पक्ष में एक हथियार बना लिया है। यह एक तरह से दबाव की कूटनीति है, जिसमें वह व्यापार समझौते की शर्तों को अपने हित में मनमर्जी तरीके से निर्धारित करना चाहता है।

संकट दूर करने को तय हो जवाबदेही



—विवेक शर्मा—



असली सवाल यह नहीं है कि हवा किसने बिगाड़ी, बल्कि यह है कि अगली सर्दी आने से पहले इसे साफ करने के लिए कौन क्या करेगा। साफ हवा सबका हक है और इसे बचाना सबकी साझा जिम्मेदारी। आंखों में जलन और गले में खराश अब उत्तर भारत की सालाना नियति बन गई हैं। सुबह खिड़की खोलते ही गुनगुनी धूप के बजाय जब स्मॉग की धुंधली चादर स्वागत करे और खुली हवा में सांस लेना भारी पड़ने लगे, तो समझ लीजिए कि वही जाना–पहचाना संकट फिर लौट आया है। यह महज मौसम का बदलना नहीं, बल्कि हमारे पर्यावरण और जनस्वास्थ्य के सामने खड़ा एक गंभीर आपातकाल है। हर साल की तरह सवाल फिर वही है कि आखिर हमारी हवा इतनी जहरीली क्यों हो रही है और इसकी जवाबदेही किसकी है?

प्रदूषण की चर्चा शुरू होते ही सबसे पहले उंगली पराली जलाने पर उठती है। इसमें दो राय नहीं कि पंजाब और हरियाणा में धान की कटाई के बाद खेतों में लगाई जाने वाली आग से उठता धुआं और सूक्ष्म कण हवा को तेजी से बिगाड़ते हैं। लेकिन इस पूरे संकट का ठीकरा केवल किसानों के सिर फोड़ना न तो न्यायसंगत है और न ही व्यावहारिक। अगली फसल की बुआई के लिए समय की कमी, मशीनों का भारी खर्च और विकल्पों का अभाव किसान की अपनी मजबूरियां हैं। उसे भरोसेमंद और सस्ता विकल्प दिए बिना केवल जुर्माने या सख्ती से बात नहीं बनेगी। सरकारों को मशीनों की उपलब्धता, किराये में सीधी मदद और पराली के औद्योगिक इस्तेमाल का ठोस तंत्र खड़ा करना होगा।

दूसरी तरफ, प्रदूषण को केवल खेतों तक सीमित करके देखना समस्या के बड़े हिस्से से आंख मूंदना है। शहरों की सड़कों पर रेंगते वाहनों का धुआं, उद्योगों का उत्सर्जन, निर्माण स्थलों से उड़ती धूल और खुले में जलता कचरा साल भर हवा में जहर घोलते हैं। टूटी सड़कों की गर्द, सिमटती हरियाली और अनियंत्रित शहरीकरण ने भी इस समस्या को और जटिल बना दिया है। नियमों की अनदेखी और लचर निगरानी ने शहरों को गैस चौंबर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है।

विडंबना यह है कि जब सांस लेना दूभर हो रहा है, तब राजनीतिक दल आरोप–प्रत्यारोप के पुराने खेल में उलझे हैं। कोई पराली को कोसता है, कोई पड़ोसी राज्य की सरकार पर निशाना साधता है तो कोई केंद्र की नीतियों को कठघरे में खड़ा करता है। लोकतंत्र में सवाल पूछना जरूरी है, पर हवा किसी राज्य की सीमा या सियासी दल का झंडा देखकर नहीं बहती। आम आदमी को इस बहस से कोई सरोकार नहीं कि किसने किस पर क्या आरोप लगाया। उसे तो बस साफ हवा चाहिए। इसके लिए पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और केंद्र को एक मेज पर बैठकर साझा कार्ययोजना बनानी ही होगी।

सर्दियों में हवा की रफ्तार थमने और तापमान गिरने से प्रदूषक जमीन के करीब ही ठहर जाते हैं, जिससे स्मॉग की परत और घनी हो जाती है। लेकिन मौसम केवल हालात को बिगाड़ता है, प्रदूषण पैदा नहीं करता। इसलिए कुदरत को दोष देकर जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ा जा सकता। जरूरत सर्दियों के तात्कालिक उपायों की नहीं, बल्कि साल भर चलने वाले नियंत्रण की है। यह संकट लाइलाज नहीं है। चीन की राजधानी बीजिंग इसका बड़ा उदाहरण है, जो कभी भयावह वायु प्रदूषण से जूझ रही थी। वर्ष 2013 के बाद वहां कोयला संयंत्रों पर लगाम कसने, स्वच्छ घरेलू ईंधन को बढ़ावा देने, उद्योगों में बदलाव करने और वाहन उत्सर्जन पर सख्त नियम लागू करने जैसे ठोस कदम उठाए गए। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) की 2019 की रिपोर्ट के अनुसार, 2013 से 2017 के बीच बीजिंग में पीएम 2.5 के स्तर में 35 प्रतिशत और आसपास के इलाकों में 25 प्रतिशत की गिरावट आई। हालांकि वहां भी हवा पूरी तरह विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों पर खरी नहीं उतरी थी, लेकिन इस अनुभव ने साबित कर दिया कि स्पष्ट नीति और सख्त अमल से तस्वीर बदली जा सकती है। जहरीली हवा की सबसे बड़ी कीमत बच्चों, बुजुर्गों और सांस व दिल के मरीजों को चुकानी पड़ती है। प्रदूषण के चरम पर पहुंचते ही स्कूल बंद करने पड़ते हैं और बच्चों का खेलकूद घर की चारदीवारी तक सिमट जाता है। अस्पतालों में मरीजों की भीड़ और इलाज का बढ़ता खर्च आम परिवारों की कमर तोड़ रहे हैं। साफ हवा कोई विलासिता नहीं, बल्कि जीवन की बुनियादी शर्त है। इसके लिए बेहतर सार्वजनिक परिवहन, स्वच्छ ऊर्जा और कचरे के वैज्ञानिक निपटान पर जोर देने से काम करना होगा। साथ ही, नागरिकों को भी निजी वाहनों का मोह छोड़कर और कचरा न जलाने जैसी छोटी–छोटी आदतें अपनाकर अपनी भूमिका निभानी होगी।

सच यह है कि प्रदूषण के लिए कोई एक पक्ष जिम्मेदार नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि जिम्मेदारी किसी की नहीं। सरकारों को योजनाओं के नतीजे सार्वजनिक करने होंगे और सियासी दलों को आरोपों से आगे बढ़कर समाधान पर एकमत होना होगा। असली सवाल यह नहीं है कि हवा किसने बिगाड़ी, बल्कि यह है कि अगली सर्दी आने से पहले इसे साफ करने के लिए कौन क्या करेगा। साफ हवा सबका हक है और इसे बचाना सबकी साझा जिम्मेदारी।

बाजार के हवाले होती भोजन की थाली से उपजा संकट



—ललित गर्ग—



भारत की पहचान केवल उसकी आध्यात्मिकता, विविधता और संस्कृति से नहीं, उसकी रसोई से भी होती है। हमारी रसोई में स्वाद के साथ स्वास्थ्य, ऋतु के साथ संतुलन और भोजन के साथ संस्कार जुड़े रहे हैं। दादी–नानी के हाथों का भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं था, वह परिवार की सेहत की पहली पाठशाला था। दाल, बाजरा, ज्वार, रागी, हरी सब्जियां, मौसमी फल, छाछ, अंकुरित अनाज, मसालों का संतुलित उपयोग और घर का ताजा भोजन भारतीय जीवन–पद्धति की ताकत रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ दशकों में हमारी थाली धीरे–धीरे बदल गई है। स्वाद के नाम पर बाजार ने हमारी रसोई में प्रवेश किया और सुविधा के नाम पर पैकेट ने घर की कड़ाही को पीछे धकेलना शुरू कर दिया। इसी बदलती खाद्य संस्कृति के बीच सुप्रीम कोर्ट का हालिया निर्देश एक महत्वपूर्ण चेतावनी की तरह सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने खाद्य पैकेटों पर फ्रंट–ऑफ–पैक पोषण लेबलिंग को मजबूत करने का निर्देश देते हुए कहा है कि अधिक शुगर, सैचुरेटेड फैट और नमक वाले उत्पादों पर अलग–अलग स्पष्ट चेतावनी चिह्न हों। न्यायालय ने 'टोटल शुगर' और 'सैचुरेटेड फैट' को प्रमुखता से दिखाने तथा 'हाई शुगर', 'हाई फैट और 'हाई साल्ट' जैसे स्पष्ट संकेत देने की दिशा में कदम उठाने को कहा है। उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है– उपभोक्ता को वह जानकारी सामने मिले, जिसे वह छोटे अक्षरों में खोजते–खोजते अक्सर छोड़ देता है। यह फैसला केवल लेबल बदलने का फैसला नहीं है, यह उस सोच को बदलने का प्रयास है जिसमें चमकदार पैकेट देखकर भोजन की गुणवत्ता तय कर ली जाती है। आज बाजार में किसी उत्पाद का विज्ञापन उसकी पौष्टिकता से अधिक आकर्षक पैकेजिंग, स्वाद और सुविधा बेचता है। बच्चे रंगीन पैकेट से आकर्षित होते हैं, युवा त्वरित भोजन को जीवनशैली समझने लगे हैं और व्यस्त परिवारों के लिए डिब्बाबंद भोजन समय बचाने का आसान विकल्प बन गया है। समस्या तब पैदा होती है जब सुविधा धीरे–धीरे आदत और आदत बीमारी में बदल जाती है। सबसे बड़ा खतरा यह है कि भोजन की अपनी थाली का प्रहरी बनना होगा। जिस प्रकार हम घर खरीदते समय कीमत, स्थान और गुणवत्ता देखते हैं, उसी प्रकार भोजन खरीदते समय उसके घटकों को देखना भी हमारी आदत बननी चाहिए। किसी पैकेट पर बड़ा 'हेल्दी' लिखा होना उसे स्वतः स्वस्थ नहीं बना देता। विज्ञापन स्वास्थ्य का प्रमाणपत्र नहीं है। असली प्रमाण उसके पोषण संबंधी विवरण और हमारी आवश्यकता के बीच संतुलन है।

बच्चों के मामले में विशेष सावधानी आवश्यक है। बच्चे विज्ञापन और पैकेजिंग से सबसे जल्दी प्रभावित होते हैं। यदि स्कूल के आसपास और डिजिटल माध्यमों पर अत्यधिक चीनी, नमक और वसा वाले खाद्य पदार्थों को आकर्षक ढंग से प्रस्तुत किया जाता रहेगा, तो स्वस्थ भोजन उनके लिए 'उबाऊ' और अस्वास्थ्यकर भोजन 'मजेदार' बन जाएगा। इसलिए स्कूलों को केवल पाठ्यपुस्तकों में स्वास्थ्य शिक्षा देने के बजाय कैंटीन और परिसर के आसपास उपलब्ध भोजन के माध्यम से भी स्वस्थ आदतें विकसित करनी होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों के आसपास ऐसे खाद्य पदार्थों और उनके विज्ञापनों पर नियंत्रण की दिशा में भी जोर दिया है। हमें यहां एक और क्रांतिकारी विचार पर काम करना होगा—'फूड लिटरेसी' को जनशिक्षा का हिस्सा बनाना। जिस तरह बच्चों को वित्तीय साक्षरता और डिजिटल साक्षरता सिखाई जा रही है, उसी तरह उन्हें खाद्य साक्षरता भी सिखाई जानी चाहिए। बच्चे जानें कि शुगर क्या करती है, अधिक नमक क्यों नुकसान पहुंचाता है, संतृप्त वसा क्या है, पैकेट पर लिखे पोषण–लेबल को कैसे पढ़ना है और ताजा स्थानीय भोजन क्यों बेहतर विकल्प हो सकता है। एक जागरूक बच्चा केवल स्वयं स्वस्थ नहीं रहेगा, वह अपने परिवार की भोजन–आदत भी बदल सकता है। साथ ही भारतीय खाद्य संस्कृति को आधुनिक रूप देकर पुनर्जीवित करने की जरूरत है। स्वस्थ भोजन का अर्थ यह नहीं कि स्वाद छोड़ दिया जाए।

भारत के पास स्वाद और स्वास्थ्य का अद्भुत संतुलन बनाने की हजारों वर्ष पुरानी क्षमता है। जरूरत है कि बाजरा, दाल, सब्जियों, पारंपरिक पेयों और स्थानीय व्यंजनों को आधुनिक प्रस्तुति, स्वच्छ पैकेजिंग और उचित मूल्य के साथ नई पीढ़ी तक पहुंचाया जाए। हमें विदेशी खाद्य संस्कृति का विरोध नहीं, बल्कि अपनी समृद्ध खाद्य संस्कृति को इतना आकर्षक बनाना है कि भारतीय युवा उसे गर्व से अपनाए। इस दिशा में एक नया सामाजिक अभियान चल सकता है—'मेरी थाली, मेरी जिम्मेदारी।' परिवार सप्ताह में कम–से–कम कुछ दिन पैकेटबंद भोजन से दूरी बनाए, स्कूल स्वस्थ भोजन दिवस मनाएं, कार्यालयों में पौष्टिक भोजन को बढ़ावा मिले, सार्वजनिक संस्थान स्थानीय और पारंपरिक खाद्य पदार्थों को प्रोत्साहित करें तथा मीडिया भोजन के विज्ञापन में केवल स्वाद नहीं, स्वास्थ्य की चेतना भी जगाए। खाद्य उद्योग को भी शत्रु मानने के बजाय जिम्मेदार भागीदार बनाया जाना चाहिए। मुनाफा कमाना उसका अधिकार है, लेकिन उपभोक्ता के स्वास्थ्य की कीमत पर मुनाफा कमाना सामाजिक रूप से स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने मूलतः एक सवाल हमारे सामने रखा है—क्या हमारी सुविधा हमारी सेहत से बड़ी हो गई है? इसका उत्तर हमें सामूहिक रूप से देना होगा। अदालत ने पैकेट के सामने चेतावनी लगाने का रास्ता दिखाया है, लेकिन असली चेतावनी हमारे विवेक पर लिखी जानी चाहिए। यदि लाल निशान देखकर भी हम वही चीज खरीदते रहें, तो केवल लेबल बदलने से समाज नहीं बदलेगा।

भारत की खाद्य संस्कृति को बचाने का अर्थ अतीत में लौटना नहीं, बल्कि परंपरा और आधुनिक विज्ञान का सुंदर समन्वय करना है। हमें ऐसी खाद्य व्यवस्था बनानी होगी जिसमें किसान को सम्मानजनक बाजार मिले, स्थानीय भोजन को प्रतिष्ठा मिले, उद्योग को जिम्मेदारी का बोध हो, बच्चों को स्वस्थ विकल्प मिलें और उपभोक्ता को पूरी जानकारी मिले। देश की वास्तविक समृद्धि केवल उसके सकल घरेलू उत्पाद से नहीं, उसके नागरिकों की स्वस्थ सांसों से मापी जानी चाहिए। हमारी रसोई बची रहेगी तो हमारी संस्कृति बचेगी हमारी थाली स्वस्थ रहेगी तो हमारा भविष्य स्वस्थ रहेगा। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्देश इसलिए केवल पैकेट पर लगने वाला लाल निशान नहीं, बल्कि हमारी बदलती खाद्य आदतों के सामने लगा हुआ एक बड़ा सामाजिक आईना है। अब फैसला हमारे हाथ में है–हम उस आईने में खतरा देखकर अपनी आदत बदलते हैं या चेतावनी पढ़कर भी उसी रास्ते पर चलते रहते हैं। समय आ गया है कि भारत 'जंक फूड की खपत' में नहीं, 'स्वस्थ भोजन की संस्कृति' में दुनिया का नेतृत्व करे। यही इस न्यायिक पहल की सबसे बड़ी और सकारात्मक परिणति हो सकती है।

भारतीय कृषि का बदलता स्वरूप



—सौरभ वार्ष्णेय—

भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है, लेकिन भारतीय कृषि की वास्तविक स्थिति आज अनेक चुनौतियों और बदलावों के दौर से गुजर रही है। खेती केवल देश की खाद्य जरूरतों को पूरा करने का माध्यम नहीं, बल्कि करोड़ों परिवारों की आजीविका, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ और देश की सामाजिक संरचना का महत्वपूर्ण आधार है। समय के साथ कृषि का स्वरूप बदला है। पारंपरिक खेती की जगह आधुनिक तकनीक, मशीनों, उन्नत बीजों, डिजिटल सेवाओं और वैज्ञानिक पद्धतियों ने लेनी शुरू कर दी है। इसके बावजूद भारतीय किसान आज भी आर्थिक असुरक्षा, मौसम की अनिश्चितता, महंगी कृषि लागत, बाजार की अस्थिरता और कर्ज जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या बदलती कृषि व्यवस्था किसान को आत्मनिर्भर बना पाएगी और क्या भारत का अन्नदाता अपनी मेहनत का उचित मूल्य प्राप्त कर सकेगा?

भारतीय कृषि में पिछले कुछ दशकों के दौरान व्यापक परिवर्तन देखने को मिले हैं। हरित क्रांति ने देश को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्नत बीजों, रासायनिक उर्वरकों, सिंचाई सुविधाओं और कृषि मशीनरी के उपयोग से उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई। आज ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर और आधुनिक कृषि उपकरण खेती का हिस्सा बन रहे हैं। कई क्षेत्रों में किसान मोबाइल फोन के माध्यम से मौसम की जानकारी, बाजार भाव और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने का प्रयास कर रहे हैं। कृषि में ड्रोन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी नई तकनीकों का प्रवेश भी भविष्य की संभावनाओं को दर्शाता है।

लेकिन तकनीकी विकास की यह तस्वीर सभी किसानों के लिए समान नहीं है। देश में बड़ी संख्या छोटे और सीमांत किसानों की है, जिनके पास सीमित कृषि भूमि और निवेश की क्षमता है। महंगे कृषि उपकरण खरीदना, आधुनिक तकनीक अपनाना और वैज्ञानिक प्रशिक्षण प्राप्त करना उनके लिए आसान नहीं है। बड़े किसानों की तुलना में छोटे किसान संसाधनों की कमी के कारण तकनीकी बदलावों का पूरा लाभ नहीं उठा पाते। इसलिए कृषि का आधुनिकीकरण तभी सार्थक होगा, जब इसका लाभ गांव के अंतिम किसान तक पहुंचे।

भारतीय किसान की सबसे बड़ी समस्या खेती की बढ़ती लागत और आमदनी के बीच असंतुलन है। डीजल, बिजली, खाद, बीज, कीटनाशक और कृषि मजदूरी की लागत लगातार खेती के आर्थिक गणित को प्रभावित करती है। इसके विपरीत फसल तैयार होने के बाद किसान को कई बार बाजार में उचित मूल्य नहीं मिल पाता। बिचौलियों की भूमिका, भंडारण की कमी और मंडियों में कीमतों का उतार–चढ़ाव उसकी आर्थिक स्थिति को और कठिन बना देता है। कई बार किसान को मजबूरी में अपनी उपज कम कीमत पर बेचनी पड़ती है। ऐसी स्थिति में उत्पादन बढ़ने के बावजूद उसकी वास्तविक आय में अपेक्षित सुधार नहीं हो पाता।

न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी का मुद्दा भी कृषि व्यवस्था के केंद्र में है। किसानों की मांग है कि उनकी प्रमुख फसलों को लाभकारी मूल्य मिले और खरीद व्यवस्था का विस्तार हो। हालांकि सरकारी खरीद की पहुंच और प्रभाव अलग–अलग राज्यों तथा फसलों में अलग–अलग है। इसलिए केवल समर्थन मूल्य घोषित करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि खरीद केंद्रों की उपलब्धता, भुगतान की समयबद्ध व्यवस्था और बाजार तक किसानों की सीधी पहुंच सुनिश्चित करना भी जरूरी है। कृषि बाजार में पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए प्रभावी नीतियों की आवश्यकता है।

जलवायु परिवर्तन भारतीय कृषि के सामने एक गंभीर चुनौती बनकर उभर रहा है। कभी अत्यधिक बारिश, कभी सूखा, कभी बेमौसम ओलावृष्टि और कभी तापमान में असामान्य वृद्धि फसलों को प्रभावित करती है। मानसून पर निर्भर किसानों के लिए मौसम की अनिश्चितता आर्थिक जोखिम बढ़ा देती है।

शादी के मंडप से भागकर परतावल पहुंची युवती, शादी के जोड़े में देख जुटी भीड़

संवाददाता–महराजगंज। परतावल चौराहे पर शनिवार को उस समय लोगों की भीड़ जुट गई, जब शादी का जोड़ा पहने एक युवती बस से उतरी। युवती को इस हालत में देखकर लोग तरह–तरह की चर्चाएं करने लगे। सूचना मिलने पर परतावल पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस युवती को चौकी पर ले गई और उससे पूछताछ की। पूछताछ के दौरान युवती ने अपनी उम्र 22 वर्ष बताई। उसने बताया कि वह बस्ती जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र की रहने वाली है। युवती के मुताबिक उसकी सौतेली मां 27 नवंबर को उसकी शादी उसकी उम्र से काफी अधिक उम्र के एक बुजुर्ग व्यक्ति से करा रही थी। इस शादी से वह सहमत नहीं थी। इसलिए वह शादी के मंडप से ही भाग निकली। युवती ने बताया कि वह पिछले कुछ दिनों से गोरखपुर में रहकर ब्यूटी पार्लर चलाने का काम करती है।इस संबंध में परतावल चौकी प्रभारी अनीश कुमार सिंह ने बताया कि युवती शादी के जोड़े में बस से परतावल चौराहे पर उतरी थी। उसे देखकर चौराहे पर भीड़ जुट गई थी। पुलिस उसे चौकी पर ले आई और पूछताछ की। पूछताछ के बाद युवती ने अपने घर जाने के लिए किराये की मांग की।

46 जोड़ों का हुआ सामूहिक विवाह

संवाददाता–श्रावस्ती। कलेक्ट्रेट स्थित तथागत हॉल में शनिवार को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 46 जोड़ों का विवाह कराया गया। शाम 5:00 बजे विभाग ने बताया कि जिला पंचायत अध्यक्ष, विधायक और जिलाधिकारी ने नवदंपतियों को विवाह प्रमाण पत्र और उपहार दिए। जनप्रतिनिधियों ने कहा कि योजना के जरिए सरकार आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों के विवाह का खर्च उठाती है। इससे माता–पिता को आर्थिक चिंता से राहत मिलती है और पात्र परिवार सम्मान के साथ विवाह कर पाते हैं। जिलाधिकारी ने नवदंपतियों को आशीर्वाद दिया। उन्होंने



कहा कि योजना गरीब परिवारों के लिए मददगार है और इससे सामाजिक समरसता व सर्वधर्म सद्भाव को बढ़ावा मिलता है। सभी जोड़ों का विवाह उनकी सामाजिक और धार्मिक मान्यताओं व परंपराओं के अनुसार कराया गया।

जिला समाज कल्याण अधिकारी अमरनाथ यति ने बताया कि समारोह में अल्पसंख्यक वर्ग के 9, अन्य पिछड़ा वर्ग के 18, अनुसूचित जाति के 11, अनुसूचित जनजाति के 4 और सामान्य वर्ग के 4 जोड़े शामिल हुए।

योजना के तहत हर जोड़े को एक लाख रुपये की सहायता दी जाती है। इसमें 60 हजार रुपये वधू के खाते में भेजे जाते हैं और 25 हजार रुपये की उपहार सामग्री दी जाती है। बाकी 15 हजार रुपये भोजन, टेंट और आयोजन की अन्य व्यवस्थाओं पर खर्च होते हैं।

योगी ने मां पाटेश्वरी की उतारी आरती, गोशाला में गायों को खिलाया गुड़ व हरा चारा, बच्चों को दी चाकलेट

संवाददाता–बलरामपुर। बलरामपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार सुबह मां पाटेश्वरी के दरबार में माथा टेका। देवीपाटन मंदिर में उन्होंने आदिशक्ति मां पाटेश्वरी के दर्शन–पूजन कर प्रदेशवासियों के सुख, शांति, अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना की। विधि–विधान से पूजा–अर्चना के बाद मुख्यमंत्री ने मां की आरती उतारी और मंदिर परिसर में मौजूद श्रद्धालुओं का अभिवादन स्वीकार किया। इस दौरान मुख्यमंत्री का आत्मीय अंदाज भी देखने को मिला। मंदिर परिसर में मौजूद बच्चे उन्हें अपने बीच देखकर उत्साहित हो उठे। बच्चे मुख्यमंत्री के पास पहुंचे तो उन्होंने उनसे बातचीत की और चॉकलेट देकर उनका उत्साह बढ़ाया। मुख्यमंत्री का बच्चों के प्रति यह स्नेहिल व्यवहार लोगों के बीच चर्चा का विषय रहा।



मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को गोंडा में युवाओं को लैपटॉप वितरित करने के बाद बलरामपुर पहुंचे थे। देवीपाटन मंदिर परिसर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के बाद उन्होंने रात में मंदिर परिसर में ही विश्राम किया। शनिवार सुबह पूजा–अर्चना के बाद मुख्यमंत्री ने मंदिर परिसर का भ्रमण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने श्रद्धालुओं की आवाजाही, सुरक्षा, सुविधाओं और साफ–सफाई की स्थिति देखी। साथ ही संबंधित लोगों को निर्देश दिए कि मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की असुविधा नहीं होनी चाहिए। मंदिर की व्यवस्थाएं सुचारु और व्यवस्थित रखी जाएं।

मंदिर भ्रमण के बाद मुख्यमंत्री गोशाला पहुंचे। यहां उन्होंने गायों को अपने हाथों से गुड़ और हरा चारा खिलाया। कुछ समय गोशाला में बिताकर गोसेवा भी की। इस दौरान मंदिर परिसर में स्थानीय लोगों, जनप्रतिनिधियों और संतों से भी उनकी मुलाकात हुई।

कार्यक्रम में महंत मिथिलेश नाथ योगी, कालीबाड़ी गोरखपुर के महंत रविंद्र दास और हनुमानगढ़ी अयोध्या के राजू दास समेत कई संत मौजूद रहे। दर्शन–पूजन, गोसेवा और मंदिर परिसर की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी के लिए रवाना हो गए।

पति को आत्महत्या के लिए उकसाने की आरोपी पत्नी गिरफ्तार



संवाददाता–बहराइच। रानीपुर पुलिस ने पति को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में करीब तीन साल से फरार आरोपी ममता को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

मामला 29 अक्टूबर 2023 का है। पुलिस के मुताबिक, रानीपुर थाना क्षेत्र के निजामपुर निवासी धर्मराज पुत्र छोटेलाल की पत्नी ममता अपने पति और तीन बच्चों को छोड़कर चली गई थी। ममता मूल रूप से हरदुआ दुर्गापुर की रहने वाली है। आरोप है कि पत्नी के इस कदम और प्रताड़ना से आहत होकर धर्मराज ने खुद और अपने तीन बच्चों रितिक, छाया और मुस्कान को कीटनाशक दवा पिला दी थी।

अस्पताल में इलाज के दौरान धर्मराज की मौत हो गई, जबकि तीनों बच्चों की जान बच गई। धर्मराज के भाई की शिकायत पर रानीपुर थाने में ममता के खिलाफ मुकदमा नंबर 213/23 दर्ज किया गया था। उस पर भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है।

घटना के बाद से ममता फरार थी। गिरफ्तारी नहीं होने पर कोर्ट ने उसके खिलाफ गैर–जमानती वारंट जारी किया और संपत्ति कुर्क करने के आदेश दिए। पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर सकी। बाद में 8 नवंबर 2025 को पुलिस ने उसकी फरारी के दौरान ही कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था।

थानाध्यक्ष हरेंद्र नाथ राय के नेतृत्व में पुलिस टीम उसकी तलाश कर रही थी। मुखबिर से सूचना मिलने पर पुलिस ने टेढ़ी पुलिया तिराहा, गड़रेयिनपुरवा मझौवा के पास से ममता को गिरफ्तार किया।

पुलिस ने कानूनी कार्रवाई पूरी करने के बाद उसे कोर्ट में पेश किया। वहां से उसे जेल भेज दिया गया।

मां की डांट से नाराज किशोरी घर से लापता, नदी में मिला शव

संवाददाता–देवरिया। थाना क्षेत्र के एक गांव में मोबाइल पर बातचीत करने को लेकर मां की डांट से नाराज किशोरी शुक्रवार को घर से कही चली गयी। शनिवार की सुबह छोटी गंडक नदी में उसका शव मिलने से गांव में सनसनी फैल गई। परिजनों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली किशोरी कुछ दिन पहले रिश्तेदारी में एक शादी समारोह में गई थी। वहां उसकी एक युवक से जान–पहचान हो गई थी। इसके बाद दोनों के बीच मोबाइल पर बातचीत होने लगी।

शुक्रवार को किशोरी मोबाइल पर बात कर रही थी। इसी दौरान उसकी मां ने उसे देख लिया और डांट–फटकार लगाई। मां की डांट से नाराज होकर किशोरी बिना किसी को बताए घर से चली गई। देर रात तक परिजन उसकी तलाश करते रहे, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला।शुक्रवार को छोटी गंडक नदी में किशोरी का शव उतराता हुआ दिखाई दिया। इसकी जानकारी मिलते ही परिजनों में चीख–पुकार मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को नदी से निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।थाना प्रभारी सदगुरु मिश्रा ने बताया कि किशोरी का शव मिला है। पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की जा रही है।

कमिश्नर और डीआईजी ने श्यामदेउरवा थाने में की सुनवाई

संवाददाता–महराजगंज। शिकायतों के त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण के उद्देश्य से शनिवार को थाना श्यामदेउरवा में थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मंडलायुक्त व पुलिस उपमहानिरीक्षक गोरखपुर ने लोगों की समस्याओं की सुनवाई की। मौके पर जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक उपस्थित रहे। थाना समाधान दिवस के दौरान अधिकारियों ने थाने पर उपस्थित फरियादियों की समस्याओं एवं शिकायतों को गंभीरतापूर्वक सुना। संबंधित प्रकरणों की जानकारी प्राप्त कर उनके निस्तारण की स्थिति की समीक्षा की गई। अधिकारियों ने शिकायतकर्ताओं से सीधे संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं को समझा और संबंधित विभागों के अधिकारियों व पुलिस अधिकारियों को शिकायतों का निष्पक्ष निस्तारण करने का निर्देश दिया। भूमि विवाद एवं राजस्व से संबंधित मामलों में राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम द्वारा मौके पर जाकर स्थलीय जांच एवं आवश्यक कार्रवाई करने पर विशेष जोर दिया गया, जिससे शिकायतों का प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जा सके। साथ ही अनावश्यक विवाद की स्थिति उत्पन्न न हो।अधिकारियों ने कहा कि थाना समाधान दिवस का उद्देश्य आमजन की समस्याओं का स्थानीय स्तर पर प्रभावी समाधान करना है। अतः प्राप्त शिकायतों के निस्तारण में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। प्रत्येक प्रकरण में नियमानुसार निष्पक्ष कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इस अवसर पर संबंधित राजस्व एवं पुलिस विभाग के अधिकारीकर्मचारी उपस्थित रहे।

मौलिक अधिकारों के हनन का आरोप लगा अधिवक्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन



संवाददाता–महराजगंज। सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष धीरेंद्र मिश्रा, महामंत्री प्रमोद त्रिपाठी व वरिष्ठ अधिवक्ता धर्मेंद्र त्रिपाठी के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने प्रदेशव्यापी चार सूत्रीय मांगों के समर्थन में शनिवार को विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन के बाद अधिवक्ताओं ने आम सभा का बैठक की। इस दौरान वादकारी हित सुरक्षित रखने का मांग पत्र जिला जज अरविंद मलिक को दिया गया। आम सभा की बैठक में महामंत्री प्रमोद त्रिपाठी ने कहा कि अधिवक्ता विरोधी कानून की वापसी तक तथा सिविल कोर्ट न्यायालय परिसर के प्रस्तावित 35 एकड़ भूमि के अधिग्रहण तक यह विरोध प्रदर्शन प्रत्येक शनिवार को जारी रहेगा। अधिवक्ता धर्मेंद्र त्रिपाठी ने कहा कि अधिवक्ता हितों का हनन करके परोक्ष रूप से फरियादियों के हितों का नुकसान पहुंचाया जा रहा है। आम सभा में उपस्थित अधिवक्ताओं ने सर्वसम्मति से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग पर जोर दिया। अधिवक्ताओं का कहना रहा कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू न होने से अधिवक्ताओं को न्यायिक सेवा संपादित करने में असुरक्षा तथा मुकदमों की पैरवी करने की रंजिश से अधिवक्ताओं पर हमले तथा फर्जी मुकदमों में फंसाया जा रहा है। अधिवक्ताओं पर हुए फर्जी मुकदमों का ट्रायल अन्य जनपद में कराये जाने से अधिवक्ताओं का न्यायिक सेवा प्रदान करना प्रभावित होगा। इसके दुरुपयोग की संभावनाओं से इंकार नहीं किया जा सकता। विरोध प्रदर्शन में पूर्व अध्यक्ष इंद्रासन सिंह, पूर्व महामंत्री धर्मेंद्र त्रिपाठी, सत्य प्रकाश सिंह, दिनेश गुप्ता, महताब, वशिष्ठ मिश्रा, सुरेंद्र सिंह गांधी, अरविंद निषाद, संतोष पटेल, दीनानाथ साहनी, संतोष वर्मा, शत्रुघ्न गुप्ता सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं ने अपनी सहभागिता सुनिश्चित की।

बर्खास्त सहायक आबकारी आयुक्त की जमानत याचिका खारिज

बीते वर्ष 2024 हुए 2.72 करोड़ के स्प्रिट चोरी, आपराधिक साजिश और गबन के मामले में सहायक आबकारी आयुक्त को बड़ा झटका लगा है। इसके आदेश की कॉपी आज शनिवार सुबह 10रू30 बजे सामने आई है जिसके बाद अब सहायक आबकारी आयुक्त रामप्रीत चौहान पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। ध्साहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अभिनव चतुर्वेदी के अनुसार जिले में तैनात तत्कालीन सहायक आबकारी आयुक्त व स्टार लाइट ब्लकेम लिमिटेड आसवनी नवाबगंज के प्रभारी अधिकारी रामप्रीत चौहान ने बीते 10 अक्टूबर 2024 को नवाबगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराया था।

उन्होंने कहा था कि 10 अक्टूबर 2024 को आसवनी के प्रतिनिधि चंद्र प्रकाश मिश्रा की सूचना पर आबकारी निरीक्षक अवधेश राय,सीपी मिश्रा और आसवनी के प्रबंधक रचित मेहरोत्रा के साथ आसवनी के ईएनए गोदाम संख्या दो का निरीक्षण किया गया।

वहां पता चला कि गोदाम के अंदर से तरल पदार्थ निकल कर नाले में बह रहा है और स्प्रिट की गंध आ रही थी। गोदाम में टंकियों के निरीक्षण में ईएनए टैंक संख्या 13 के वाल्व के पास नीचे से स्प्रिट बह रहा था। डिप की नाप मात्र एक सेमी मिली, जिससे स्प्रिट की कोई मात्रा नहीं पाई गई। रिकॉर्ड के अनुसार टैंक संख्या 13 में रखी कुल 22610 बल्क लीटर ग्रीन ईएनए बह जाने से दो करोड़ 72 लाख 80 हजार 568 रुपये की राजस्व क्षति हुई है। जगदीश अग्रवाल,प्रबंधक रचित मेहरोत्रा,केमिस्ट सह एजेंट चंद्र प्रकाश मिश्र,बाटलिंग मैनेजर अमित ठाकुर, सुपरवाइजर अंकित अग्रवाल और अन्य के विरुद्ध केस दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की थी। वेवचना में सबूत के आधार पर वादी मुकदमा सहायक आबकारी आयुक्त रामप्रीत चौहान का भी नाम प्रकाश में आया। बीते 2 जनवरी 2025 को रामप्रीत चौहान को आबकारी मंत्री द्वारा निलंबित कर दिया गया था और पूरे मामले की जांच विशेष सचिव दिव्य प्रकाश गिरी को दी गई थी। जांच में दोषी मिलने पर इन्हें नवंबर 2025 में बर्खास्त कर दिया गया था।

खड़े ट्रक में पीछे से घुसी कार, मां–बेटे की मौत, गेट काटकर निकाले गए शव

संवाददाता–बलरामपुर। बलरामपुर–बहराइच रोड पर शनिवार सुबह तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़े ट्रक में पीछे से जा घुसी। टक्कर इतनी भीषण थी कि टाटा नेक्सॉन कार के परखच्चे उड़ गए। मां–बेटे के शव कार का दरवाजा काटकर बाहर निकाले गए। हादसे में 7 साल की बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसा जिला मुख्यालय से 13 किलोमीटर दूर कोतवाली देहात क्षेत्र चौकी चकवा के कल्ला भट्ठा के पास सुबह करीब 9:30 बजे हुआ। परिवार लखीमपुर में शादी समारोह में शामिल होकर बिहार लौट रहा था। हादसे के बाद बच्चों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।



पश्चिमी चंपारण (बिहार) के बेतिया स्थित ठाकुराई टोला निवासी अखिलेश कुमार (45) मां पूनम, बेटे दिव्यांश और बेटी निष्ठा के साथ लखीमपुर में एक शादी समारोह में शामिल होने गए थे। शादी 26 नवंबर को थी। शनिवार सुबह पूरा परिवार कार से वापस घर लौट रहा था। सुबह करीब 9:30 बजे उनकी कार बलरामपुर–बहराइच रोड पर कल्ला भट्ठा के पास पहुंची। इसी दौरान तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़े ट्रक में पीछे से जा घुसी। हादसे के बाद मौके पर चीख–पुकार मच गई। आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। बेटे अखिलेश और मां पूनम की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, बेटी निष्ठा गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने दोनों बच्चों को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। घायल बेटी निष्ठा ने बताया कि वह अपनी मौसी की शादी में शामिल होने के लिए नानी के घर गई थी। शादी 26 नवंबर को हुई थी। शनिवार सुबह करीब 4 बजे वह परिजनों के साथ नानी के घर से निकली थी। इसके बाद हादसा कैसे हुआ, उसे कुछ भी याद नहीं है। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली देहात गिरजेश तिवारी ने बताया कि मृतकों और घायलों के परिजनों को सूचना दे दी गई है।

सेवा के प्रतिमूर्ति थे श्री महंत रामविलास दास महाराज -महंत परशुराम दास



11वीं पुण्यतिथि पर संत–महंतों एवं श्रद्धालुओं ने अर्पित की भावपूर्ण श्रद्धांजलि सुंदरकांड पाठ का हुआ आयोजन

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

अयोध्या। धर्मपथ स्थित सिद्धपीठ श्री संकट मोचन हनुमान किला मंदिर के संस्थापक एवं साकेतवासी श्री महंत रामविलास दास महाराज की 11वीं पुण्यतिथि शनिवार को श्रद्धा, भक्ति एवं भावपूर्ण वातावरण में मनाई गई। उनके साथ अखिल भारतीय चतुःसम्प्रदाय के अध्यक्ष कायाकल्पी संत बर्फानी दादा लाल बिहारी दास, महंत अर्जुन दास सहित अन्य संत को भी नमन किया गया।इस अवसर पर सुंदरकांड पाठ, श्रद्धांजलि सभा एवं संत समागम का आयोजन हुआ, जिसमें अयोध्या के बड़ी संख्या में संत–महंतों, धर्माचार्यों एवं श्रद्धालुओं ने सहभागिता कर दिवंगत महंत को श्रद्धासुमन अर्पित किए।कार्यक्रम का संयोजन श्री महंत रामदास एवं महंत परशुराम दास महाराज ने किया। श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए श्री संकट मोचन हनुमान किला मंदिर के महंत परशुराम दास महाराज ने कहा कि श्री महंत रामविलास दास महाराज सेवा, परमार्थ एवं करुणा के साक्षात प्रतिमूर्ति थे। बाईपास स्थित अपने आश्रम में वह संतों, असहायों एवं जरूरतमंदों की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहते थे। सेवा को ही परम धर्म मानने वाले महाराज जी अपने शिष्यों एवं भक्तों को भी निस्वार्थ भाव से मानव सेवा करने की प्रेरणा देते रहे। महंत परशुराम दास ने कहा कि महाराज जी का जीवन भजन, साधना एवं परोपकार को समर्पित था। उनके उपदेशों में सदैव यही भाव प्रमुख रहा कि परमात्मा की प्राप्ति का सहज मार्ग परमार्थ एवं निस्वार्थ सेवा है। आश्रम में आने वाले गरीब, असहाय एवं भटके हुए लोगों को वह आत्मीयता से आश्रय एवं सहयोग प्रदान करते थे। उनका सेवाभावी जीवन आज भी संत समाज एवं श्रद्धालुओं के लिए प्रेरणास्रोत है।पुण्यतिथि समारोह में खाक चौक के श्री महंत बृजमोहन दास, मुख्य पुजारी रामचरण दास, श्री राम वल्लभा कुंज के अधिकारी राजकुमार दास, संकट मोचन सेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत संजय दास, अनी अखाड़ा के श्री महंत मुरली दास, महंत डॉ. महेश दास, बड़े भक्तमाल के महंत अवधेश कुमार दास, महंत इंद्रदेव दास, वरिष्ठ पुजारी हेमंत दास, बड़े हनुमान के अधिकारी छविराम दास, महंत बलराम दास, महंत रामप्रकाश दास, महंत अवध किशोर शरण, महंत रामकुमार दास, बालयोगी महंत रामदास, बालयोगी महंत विनोद दास, महंत कमला दास रामायणी, महंत राघव दास, महंत मनीष दास, हनुमानगढ़ी के मुख्य पुजारी रमेश दास, महंत जन्मे जय शरण, महंत डॉ. जयरामदास वेदांती, महंत राममिलन शरण, महंत गणेशानंद दास, महंत अयोध्या दास, महंत गिरिश दास, महंत दामोदर दास एवं महंत विजय रामदास सहित बड़ी संख्या में संत–महंत उपस्थित रहे।इस अवसर पर रुदौली विधायक रामचंद्र यादव, पूर्व सांसद लल्लू सिंह के पुत्र विकास सिंह, पूर्व विधायक इंद्र प्रताप तिवारी खब्बू, अमर सिंह, विनोद सिंह, डॉ. एम.पी. यादव, पार्षद अंकित त्रिपाठी, श्री चंद्र यादव सहित अनेक श्रद्धालुओं ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों एवं संत–महंतों का स्वागत–सम्मान महंत परशुराम दास महाराज ने किया।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने सुनी समस्या, कार्रवाई के दिए निर्देश



संवाददाता–महराजगंज। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने शनिवार को अपने महराजगंज स्थित आवास पर जनता दर्शन के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों से आए नागरिकों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं। इस दौरान उन्होंने लोगों की शिकायतों, मांगों और सुझावों को गंभीरता से सुनते हुए उनके त्वरित समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। अधिकारियों से जनसमस्याओं का समयबद्ध और प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित करने को कहा। जनता दर्शन में जिले के अलग–अलग क्षेत्रों से पहुंचे लोगों ने अपनी समस्याएं रखीं। विभिन्न विभागों से जुड़ी शिकायतों और स्थानीय स्तर पर लंबित कार्यों के संबंध में भी लोगों ने अपनी बात रखी।

प्रदेश अध्यक्ष ने संबंधित अधिकारियों को प्रकरणों के निस्तारण के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनता की समस्याओं के समाधान में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए। जनता दर्शन के दौरान उन्होंने फरियाद लेकर आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बात रखने का अवसर दिया। लोगों को भरोसा दिलाया कि जनहित से जुड़े मामलों में संबंधित अधिकारियों से संवाद कर समाधान का हरसंभव प्रयास किया जाएगा।इसी क्रम में पंकज चौधरी ने पनियरा के विधायक ज्ञानेंद्र सिंह के परतावल स्थित जनसंपर्क कार्यालय पर भी पहुंचकर क्षेत्रीय नागरिकों से संवाद किया। यहां उन्होंने विभिन्न गांवों और क्षेत्रों से आए लोगों की समस्याओं, सुझावों और अपेक्षाओं को जाना। स्थानीय नागरिकों ने क्षेत्र से जुड़े विभिन्न मुद्दों को उनके सामने रखा। उन्होंने लोगों की बात सुनते हुए जनहित के विषयों पर चर्चा की और समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक पहल का भरोसा दिलाया। जनप्रतिनिधि के रूप में लोगों के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं को सुनना और समाधान की दिशा में पहल करना जरूरी है। इस दौरान पनियरा विधायक ज्ञानेंद्र सिंह, सतीश मद्धेशिया, दिनेश चन्द्र त्रिपाठी और आनंद शंकर आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे।

केवल बूथ तक न रहें सीमित, घर-घर पहुंच भरवाएं फार्म -कमिश्नर

संवाददाता–महराजगंज। कमिश्नर इंद्र विक्रम सिंह व डीआईजी एस. चन्पा ने शनिवार को श्यामदेउरवा थाने में जनसुनवाई करने के बाद परतावल के छातीराम प्राथमिक विद्यालीय में विशेष मतदाता पुनरीक्षण अभियान के तहत बूथ का निरीक्षण किया। डीएम शिवशरणप्पा जीएन व एसपी शक्ति मोहन अवस्थी के साथ बूथ पर पहुंचे इन आला अफसरों ने बूथ संख्या 332 की बीएलओ जुर्केसा से मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य की प्रगति जानी। बीएलओ को स्पष्ट निर्देश दिया कि एक जनवरी 2027 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले सभी युवाओं का नाम मतदाता सूची में शामिल कराया जाए। इसके लिए केवल बूथ पर बैठकर फार्म भरने तक सीमित न रहें, बल्कि घर–घर जाकर पात्र युवाओं की तलाश करें और उनका फार्म भरवाएं। कमिश्नर ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रत्येक पात्र नागरिक की भागीदारी जरूरी है। इसलिए कोई भी पात्र युवा मतदाता सूची में नाम दर्ज होने से वंचित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने बीएलओ से क्षेत्र में घर–घर संपर्क करने, नए मतदाताओं को चिह्नित करने और निर्धारित प्रक्रिया के तहत उनके फार्म भरवाने को कहा। निरीक्षण के दौरान मतदाता सूची में महिला और पुरुष मतदाताओं के अनुपात को बेहतर करने पर भी जोर दिया गया। उन्होंने बीएलओ द्वारा फार्म भरने की जानकारी ली तो बताया गया कि शनिवार को अब तक केवल 4 फार्म भरे गए हैं। इस पर कमिश्नर ने कहा कि इस बूथ के रेसियो के अनुसार 25 से 30 फार्म आने चाहिए। उन्होंने बताया कि आबादी के 100 लोगों में 64 प्रतिशत लोग वोटर हैं। अनुपात का आंकलन कर जनसंख्या के हिसाब से पता कर छुटे हुए वोटरों को जोड़ें। उन्होंने कहा कि 18 से 22 वर्ष के युवाओं की तलाश करें। पिछले 5 वर्षों पूर्व भी जो वोटर नहीं रहें होंगे उनका नाम इस बार न छुटने पाए।



अभियान में तेजी लाने के लिए कमिश्नर ने बूथ पर मौजूद एक आशा को भी तत्काल बीएलओ के सहयोग में लगाने का निर्देश उपजिलाधिकारी को दिया। बताया गया कि संबंधित आशा कार्यकर्ता पूर्व में बीएलओ का कार्य कर चुकी हैं। उनके अनुभव का लाभ लेकर मतदाता पुनरीक्षण अभियान को गति देने की बात कही गई। मतदाता अभियान के निरीक्षण के बाद कमिश्नर प्राथमिक विद्यालय की कक्षा में पहुंचे तो उनका अलग ही अंदाज देखने को मिला। उन्होंने बच्चों के बीच पहुंचकर औपचारिकता छोड़ दी और बिल्कुल बच्चों की तरह उनसे घुल–मिलकर बातचीत करने लगे। उन्होंने बच्चों से कविताएं सुनीं और खुद भी कविता सुनाकर उनका उत्साह बढ़ाया। इस दौरान कुछ बच्चों ने उन्हें कहानियां भी सुनाईं। बच्चों की प्रतिभा और आत्मविश्वास देखकर कमिश्नर काफी प्रसन्न नजर आए। उन्होंने बच्चों की सराहना करते हुए उन्हें पढ़ाई के साथ अपनी प्रतिभा निखारने के लिए प्रोत्साहित किया। कमीश्नर ने जानी जानी एस पापा सुना बच्चों को भी मनोरंजन कराया।

गोरखपुर-बस्ती मंडलः परिसीमन से बदलेगा सियासी नक्शा बढ़ेंगी सीटें, सीमाओं का भी होगा नए सिरे से निर्धारण

संवाददाता—गोरखपुर। केंद्र सरकार के प्रस्तावित परिसीमन विधेयक से गोरखपुर और बस्ती मंडल का सियासी नक्शा बदल सकता है। लोकसभा और विधानसभा सीटों की संख्या में 50 प्रतिशत बढ़ोतरी के प्रस्ताव के साथ ही निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का नए सिरे से निर्धारण भी होगा। इसका असर दोनों मंडलों के सात जिलों के मतदाताओं, जनप्रतिनिधियों और राजनीतिक समीकरणों पर पड़ सकता है। हालांकि, किस जिले में कितनी सीटें बढ़ेंगी और कौन-सा क्षेत्र किस विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र में शामिल होगा, यह परिसीमन आयोग की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगा। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को संविधान के 132वें संशोधन विधेयक और परिसीमन विधेयक, 2026 को मंजूरी दी है। प्रस्ताव के अनुसार, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा सीटों की मौजूदा संख्या में 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाएगी। राज्यों की विधानसभाओं की सीटें भी 50 प्रतिशत बढ़ाने का प्रस्ताव है। इसके लिए लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 850 और राज्य विधानसभाओं की अधिकतम सदस्य संख्या 650 करने की व्यवस्था प्रस्तावित है। विधेयकों पर संसद के विशेष सत्र में 30 नवंबर से चर्चा होनी है। अभी इन्हें संसद की मंजूरी मिलना बाकी है।

गोरखपुर मंडल के चार जिलों में वर्तमान में कुल 28 विधानसभा क्षेत्र हैं। इनमें गोरखपुर की नौ, देवरिया की सात, कुशीनगर की सात और महराजगंज की पांच सीटें शामिल हैं। वहीं, इन जिलों से जुड़े छह लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं। इनमें गोरखपुर, बांसगांव, देवरिया, सलेमपुर, कुशीनगर और महराजगंज शामिल हैं। बस्ती मंडल के तीन जिलों में कुल 13 विधानसभा सीटें हैं। बस्ती जिले में हर्रैया, कप्तानगंज, रुधौली, बस्ती सदर और महादेवा सहित पांच सीटें हैं। संतकबीरनगर में मेंहदावल, खलीलाबाद और धनघटा तीन विधानसभा क्षेत्र हैं। सिद्धार्थनगर में शोहरतगढ़, कपिलवस्तु, बांसी, इटवा और डुमरियागंज पांच सीटें हैं। इन तीनों जिलों से बस्ती, संतकबीरनगर और डुमरियागंज लोकसभा क्षेत्र जुड़े हैं। इस तरह दोनों मंडलों में मौजूदा विधानसभा सीटों की संख्या 41 और लोकसभा क्षेत्रों की संख्या नौ है। प्रस्ताव में सीटों की संख्या बढ़ाने का जो प्रावधान है उस आधार पर विधानसभा की सीटें बढ़कर 61 और लोकसभा सीटें 13–14 हो सकती हैं। राज्य की कुल सीटों में प्रस्तावित वृद्धि के बाद नए निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण जनसंख्या और परिसीमन आयोग के मानकों के आधार पर होगा।

परिसीमन का असर केवल सीटों की संख्या तक सीमित नहीं रहेगा। नए सिरे से निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं तय होने पर गांवों, कस्बों और शहरी इलाकों का विधानसभा क्षेत्रों में जुड़ाव बदल सकता है। कुछ गांव एक विधानसभा क्षेत्र से दूसरे में जा सकते हैं। इसी तरह लोकसभा क्षेत्रों में शामिल विधानसभा क्षेत्रों का संयोजन भी बदल सकता है। इससे स्थानीय जनप्रतिनिधियों के कार्यक्षेत्र और मतदाताओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व में बदलाव संभव है।

प्रस्तावित व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने से जुड़ा है। परिसीमन के बाद महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों का निर्धारण भी किया जाएगा। इसके साथ ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की पहचान नए सिरे से होगी। कौन-सी सीट महिला या आरक्षित श्रेणी में आएगी, इसका फैसला आयोग करेगा। ऐसे में गोरखपुर–बस्ती मंडल में यदि कुल सीटें बढ़कर 61 हो जाती हैं तो महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें 20 के करीब पहुंच जाएंगी।

प्रस्तावित विधेयकों के अनुसार, परिसीमन आयोग निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं तय करेगा। आयोग की ओर से प्रस्ताव तैयार होने के बाद संबंधित राज्यों में सुनवाई और सुझाव की प्रक्रिया भी होगी। इसके बाद अंतिम आदेश जारी किए जाएंगे।

एसएसबी ने बढ़नी–पचपेड़वा मार्ग पर 3.85 क्विंटल चाइनीज लहसुन बरामद किया



संवाददाता—सिद्धार्थनगर। भारत–नेपाल सीमा पर तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत 50वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) के जवानों ने बड़ी कार्रवाई की है। त्रिलोकपुर चौकी के जवानों ने बढ़नी–पचपेड़वा मार्ग पर बोलेरो से 3.85 क्विंटल चाइनीज लहसुन बरामद किया। इस दौरान वाहन में सवार तीन लोगों को हिरासत में लेकर बरामद लहसुन और वाहन सहित कस्टम कार्यालय बढ़नी के सुपुर्द कर दिया गया। बढ़नी–पचपेड़वा मार्ग पर त्रिलोकपुर चौकी के निकट एसएसबी के जवान नियमित जांच कर रहे थे। इसी दौरान बढ़नी की ओर से पचपेड़वा जा रही एक बोलेरो को रोककर तलाशी ली गई। वाहन में लदा सामान देखकर जवानों ने चालक और उसमें सवार लोगों से पूछताछ की। हालांकि, वे सामान के संबंध में कोई संतोषजनक जानकारी नहीं दे सके। उनके पास लहसुन से संबंधित वैध बिल, सीमा शुल्क भुगतान का प्रमाण अथवा अन्य आवश्यक अभिलेख भी नहीं थे। पूछताछ में वाहन सवार लोगों ने बताया कि बोलेरो में 3.85 क्विंटल चाइनीज लहसुन लदा है, जिसे बिक्री के लिए गोंडा ले जाया जा रहा था। आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराने पर एसएसबी जवानों ने लहसुन को संदिग्ध रूप से अवैध तरीके से ले जाए जाने के मामले में वाहन समेत कब्जे में ले लिया।

इसके बाद बोलेरो को 50वीं वाहिनी के बढ़नी स्थित सीमा चौकी भेजा गया। कार्रवाई के दौरान पकड़े गए लोगों की पहचान 71 वर्षीय खलील अहमद और 26 वर्षीय मिराज निवासी जनपद गोंडा तथा 24 वर्षीय समीर निवासी जनपद बलरामपुर के रूप में हुई। एसएसबी ने तीनों आरोपितों को बरामद 3.85 क्विंटल विदेशी लहसुन और बोलेरो सहित कस्टम कार्यालय बढ़नी को सौंप दिया। कस्टम विभाग की ओर से मामले में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।

अयोध्या पहुंचे बिहार के डिप्टी सीएम, बोले–मिथिलावासी हूं, भगवान राम से विशेष जुड़ाव

संवाददाता—अयोध्या। बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी शनिवार को रामनगरी अयोध्या पहुंचे। यहां उन्होंने भगवान राम के प्रति अपनी विशेष आस्था व्यक्त करते हुए कहा कि मिथिलावासी होने के नाते उनका प्रभु श्रीराम से गहरा जुड़ाव है। बिहार माता सीता की धरती है और भगवान राम का ससुराल है। ऐसे में अयोध्या पहुंचकर मन पुलकित हो जाता है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि सबसे पहले हनुमानगढ़ी में बजरंगबली के दर्शन करेंगे। इसके बाद रामलला के दरबार में पहुंचकर उनका आशीर्वाद लेंगे। उन्होंने भगवान राम से बिहार की उन्नति, प्रगति और समृद्धि की कामना करने की बात कही। परिसीमन बिल को लेकर पूछे गए सवाल पर विजय कुमार चौधरी ने कहा कि महिला आरक्षण कानून वर्ष 2023 में ही सर्वसम्मति से पारित हो चुका है। ऐसे में अब विपक्ष की ओर से इस पर अड़ंगा लगाने की बात समझ से परे है।



उन्होंने महिला सशक्तीकरण के मुद्दे पर बिहार सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि पंचायतों में महिलाओं को 50 प्रतिशत और सरकारी नौकरियों में 35 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। उनके मुताबिक, महिलाओं को राजनीतिक और रोजगार के क्षेत्र में अवसर देने के लिए सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।

उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व की सराहना की। कहा कि योगी सरकार में प्रदेश में विकास के कई कार्य हुए हैं। डबल इंजन की सरकार लगातार विकास के लिए काम कर रही है।

विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि एनडीए से मुकाबला करने से पहले विपक्ष को आपस में लड़ने से फुर्सत मिलनी चाहिए। मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों में विपक्ष का कोई भी दल मुकाबले में नजर नहीं आ रहा है। अयोध्या में भगवान राम के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करने के साथ ही उन्होंने बिहार की समृद्धि और विकास की कामना की।

एडीजी ने बढ़नी सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था परखी

संवाददाता—सिद्धार्थनगर। एडीजी रामकुमार ने शनिवार को भारत–नेपाल के बढ़नी सीमा क्षेत्र का औचक निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने सीमा पर तैनात सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) के अधिकारियों और जवानों से सुरक्षा संबंधी तैयारियों की जानकारी ली।

एडीजी ने एसएसबी के अधिकारियों के साथ संक्षिप्त बैठक कर सीमा पर निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने जवानों को सीमा पर सतर्कता बरतने और संदिग्ध गतिविधियों पर विशेष नजर रखने के निर्देश दिए। साथ ही सीमा से होने वाले आवागमन पर निगरानी रखने को कहा।

उन्होंने बॉर्डर चेक पोस्ट पर भारत और नेपाल के बीच आवागमन की व्यवस्था तथा आने–जाने वाले लोगों की जांच प्रक्रिया के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। निरीक्षण के दौरान सीमा सुरक्षा से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई।

ट्रक से टकराई शादी से लौट रहे परिवार की कार, मासूम समेत दो की मौत



संवाददाता—अम्बेडकरनगर। शनिवार को आगरा के पास यमुना एक्सप्रेसवे पर एक कार सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई। हादसे में सात वर्षीय मासूम समेत दो लोगों की मौत हो गई, जबकि तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे में अहिरौली थाना क्षेत्र के गोपालपुर निवासी विकास सिंह के सात वर्षीय बेटे सत्या सिंह और उनके ससुर विनोद सिंह (56) की जान चली गई। विकास की पत्नी साधना सिंह (32), उनकी मां और चचेरे भाई समेत तीन लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। परिजनों के मुताबिक, विकास सिंह का परिवार 25 नवंबर को दिल्ली में आयोजित एक शादी समारोह में शामिल होने गया था। शनिवार को परिवार को आजमगढ़ में आयोजित भतीजे के रिसेप्शन में शामिल होना था। इसी के लिए सभी लोग कार से वापस लौट रहे थे।

बताया गया कि आगरा के निकट यमुना एक्सप्रेसवे पर उनकी कार सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई। टक्कर इतनी गंभीर थी कि कार में सवार लोग घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा–तफरी मच गई।

हादसे की सूचना पर घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। वहां चिकित्सकों ने सात वर्षीय सत्या सिंह और उनके नाना विनोद सिंह को मृत घोषित कर दिया। वहीं साधना सिंह समेत तीन घायलों का उपचार चल रहा है। परिवार में दो लोगों की मौत से कोहराम मचा हुआ है।

सीओ लक्ष्मीकांत मिश्रा ने बताया कि सड़क हादसा आगरा में हुआ है। इस संबंध में परिजनों की ओर से पुलिस को कोई सूचना नहीं दी गई है।

महिला नेतृत्व विकास के लिए नारी को प्रशिक्षित किया



संवाददाता—अम्बेडकरनगर। जलालपुर ब्लॉक में जन शिक्षण केंद्र द्वारा संचालित ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम के तहत नारी संघ लीडरों का एक दिवसीय प्रशिक्षण बीआरसी कार्यालय मालीपुर में आयोजित किया गया। प्रशिक्षण का मुख्य विषय ष्समुदाय को संगठित करना, महिला नेतृत्व विकास की राजनीति एवं दृष्टिकोण्ष रहा। संस्था की सचिव पुष्पा पाल ने प्रतिभागी लीडरों को संबोधित करते हुए कहा कि किसी भी सामाजिक मुद्दे पर प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए स्पष्ट रणनीति, सही दृष्टिकोण, सामूहिक भागीदारी और निरंतर प्रयास आवश्यक हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होकर संगठित होना होगा और समुदाय की समस्याओं के समाधान के लिए सामूहिक नेतृत्व के साथ आगे आना होगा। प्रशिक्षण के दौरान लीडरों को समुदाय की समस्याओं को समझने, महिलाओं को संगठित करने, संबंधित विभागों एवं अधिकारियों से संवाद स्थापित करने तथा समस्याओं के समाधान के लिए योजनाबद्ध तरीके से पहल करने की जानकारी दी गई। विभिन्न गतिविधियों एवं सामूहिक चर्चाओं के माध्यम से प्रतिभागियों की नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास, निर्णय लेने की क्षमता और संगठनात्मक समझ विकसित करने पर विशेष जोर दिया गया। लीडरों ने सक्रिय सहभागिता करते हुए अपने अनुभव साझा किए और सीखी गई रणनीतियों को ग्राम स्तर पर लागू करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम को सफल बनाने में नारी संघ की किरमती, अनीता, हीरावती, चंद्रमा, सुगीता एवं सावित्री सहित जन शिक्षण केंद्र की पुनीता, रामहित, चांदतारा और हेमलता की सक्रिय सहभागिता रही।

खाद कारखाने से गैस रिसाव का आरोप, तीन गांवों के लोगों ने घेरा गेट, फसलें जलने का दावा

संवाददाता—गोरखपुर। चौरीचौरा क्षेत्र के देवकहिया गांव स्थित एशियन फर्टिलाइजर से शनिवार सुबह सल्फ्यूरिक एसिड के रिसाव का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने फैक्टरी गेट का घेराव किया। ग्रामीणों का कहना है कि सुबह करीब सात बजे शुरू हुआ रिसाव दो घंटे तक जारी रहा। इससे देवकहिया, अवधपुर और देवीपुर गांवों तक दुर्गंध और गैस का असर पहुंचा। लोगों को घुटन महसूस होने लगी। सूचना मिलने पर एसडीएम रवि कुमार सिंह, सीओ कुंदन कुमार सिंह, प्रभारी निरीक्षक चंद्रभूषण प्रजापति पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने फैक्टरी प्रबंधन के खिलाफ विरोध जताते हुए कार्रवाई और नुकसान के मुआवजे की मांग की।

ग्रामीणों का आरोप है कि घनी आबादी के बीच संचालित इस फैक्टरी से पिछले करीब दो दशक से आसपास के गांवों के लोग प्रभावित हो रहे हैं। उनका कहना है कि रिसाव के कारण फसलें खराब हो रही हैं और लोगों के स्वास्थ्य पर भी असर पड़ रहा है। इसके बावजूद समस्या का स्थायी समाधान नहीं



किया गया। ग्रामीणों ने बताया कि 18 अगस्त 2025 को भी फैक्टरी से गैस रिसाव हुआ था। उस समय अधिकारियों की जांच में शिकायतें सही पाए जाने के बाद प्लांट को करीब पांच महीने तक बंद रखा गया था। दोबारा संचालन शुरू होने के बाद शनिवार सुबह फिर रिसाव होने का आरोप लगाया गया है। अवधपुर गांव के किसान राजन पांडेय ने दावा किया कि रिसाव से उनकी सरसों की फसल जल गई है। इससे उन्हें करीब 50 हजार रुपये का नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि फैक्टरी के कारण किसानों की फसलों को लगातार नुकसान पहुंच रहा है। प्रशासन को फैक्टरी के खिलाफ कार्रवाई करने के साथ प्रभावित किसानों को मुआवजा दिलाना चाहिए। उधर, फैक्टरी प्रबंधन की ओर से आरोप लगाया गया कि कुछ ग्रामीण प्लांट में घुस गए और वहां काम कर रहे कर्मचारियों के साथ मारपीट की। हालांकि, इस संबंध में आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। एसडीएम रवि कुमार सिंह ने बताया कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को मामले की जांच कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम, नायब तहसीलदार और पुलिस की संयुक्त टीम जांच कर रही है। रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

अदालती नोटिस

सम्मन बरगज इनफिसाल मुकदमा (आर्डर 5 कायदा 1 व 5 मजमुआ जाप्ता 200 ई0)
नि0 सं0–C/20261700000267
धारा 210 उ0प्र0रा0सं0–2006
अदालत– श्रीमान अपर आयुक्त (प्रशासन) बस्ती मण्डल महोदय बस्ती जिला बस्ती
साधू आदि
बनाम
अ0ग्रु0प्र0स0 आदि
1. अ0ग्रु0प्र0स0 ग्राम पंचायत शंकरपुर 2. दीप कुमार सिंह पुत्र ओम प्रकाश सिंह 3. श्रवण कुमार सिंह पुत्र बेनीमाधव साकिन चन्दोखा 4. रईश मोहम्मद पुत्र दीन मोहम्मद 5. लुल्लुर पुत्र मोखई 6. सूर्यनारायन पुत्र बलेसर साकिन शंकरपुर 7. जाकिरून्निशा पत्नी सफात अली 8. शहजादी पत्नी रिसाल साकिन शंकरपुर तप्पा भानपुर परगना रसूलपुर तहसील भानपुर जिला बस्ती
तारीख पेशी 16–12–2026
वाजेह हो कि ने आपके नाम एक नालिस बाबत दायर की है। लिहाजा आपको हुक्म होता है कि आप बतारीख 16 माह 12 सन 2026 ई0 बवक्त 10 बजे दिन बमुकाम असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमे के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके हाजिरी के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तेमाल करना चाहते हों पेश करें।
आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।
बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख 26 माह 11 सन 2026 ई0 जारी किया गया।
—द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब
(आर्डर 5 कायदा 1 व 5)
अदालत–श्रीमान ग्राम न्यायालय भानपुर बस्ती जिला–बस्ती
मूलवाद सं0–298/2023
श्रीमती पुष्पा देवी
बनाम
धर्मराज आदि
4. दिलीप कुमार उम्र लगभग 40 साल 5. प्रेम कुमार उम्र लगभग 30 साल पुत्रगण रामराज 7. श्रीमती धुपा देवी उम्र लगभग 60 साल पत्नी रामराज साकिनान मौजा बनगवा तप्पा छपिया परगना रसूलपुर तहसील भानपुर पोस्ट असनहरा जिला बस्ती पिन कोड 272194
–प्रतिवादी तृतीय वर्ग
12. रामजतन उम्र लगभग 60 साल पुत्र जगमोहन साकिन करौता तप्पा सागरा परगना रसूलपुर तहसील डुमरियागंज जिला सिद्धार्थनगर
–प्रतिवादी तृतीय वर्ग
तारीख पेशी 21–12–2026
हरगाह ने आपके नाम नालिश बाबत के दायर की है। लिहाजा आपक 21 माह 12 सन 2026 ई0 बवक्त 10 बजे दिन असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमें के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके इजहार के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तेमाल करना चाहते हों पेश करें।
आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।
बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

रोजगार मेले में 553 बेरोजगारों का चयन किया गया

संवाददाता—अम्बेडकरनगर। बाबा बरुआ दास पीजी कालेज परुइया आश्रम जलालपुर में शनिवार को जिला सेवायोजन कार्यालय के तत्वावधान में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। मेले में निजी कंपनियों द्वारा 553 बेरोजगारों का चयन किया गया। मेला कार्यक्रम का शुभारंभ विधायक कटेहरी धर्मराज निषाद ने दीप प्रज्वलन कर किया। मुख्य अतिथि धर्मराज निषाद ने अपने संबोधन में कहा कि युवा मेरे देश का भविष्य है और इसे आत्मनिर्भर सशक्त बनाने में ये कार्यक्रम मील का पत्थर साबित होते हैं। जिला सेवायोजन अधिकारी अनुपमा रानी ने कहा कि शिक्षा के साथ–साथ व्यावसायिक व रोजगार परक अवसरों का मिलना छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। रोजगार मेले में विभिन्न प्रतिष्ठित 17 निजी कम्पनियों और उद्योगों ने हिस्सा लिया। मेले में कालेज एवं क्षेत्र के हजारों छात्र छात्राओं ने पूरे उत्साह के साथ पंजीकरण कराया और अपने बायोडाटा के साथ साक्षात्कार प्रक्रिया में भाग लिया। कम्पनियों के प्रतिनिधियों ने 885 में 553 का साक्षात्कार के माध्यम से योग्य युवाओं का चयन किया। कार्यक्रम का संचालन डा. रमेश कुमार व डा. अखिलेश यादव ने किया। रोजगार मेले में सरस्वती वंदना डा० अपूर्वा चतुर्वेदी एवं स्वागत गीत स्नेहा एवं खुशबू गुप्ता ने प्रस्तुत किया। जगदीश नारायण द्विवेदी ने गीत प्रस्तुत किया और नूर फातिमा, फिरदौस जहरा ने गजल प्रस्तुत किया इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि महंत देवेन्द्र दास, प्राचार्य परेश कुमार पाण्डेय, उपप्राचार्य प्रो० पवन कुमार गुप्त, सह आयोजक चन्द्रशेखर नोडल, प्रधानाचार्य विनोद सिंह, प्रधानाचार्य राजकीय आईटीआई जहांगीरगंज डा.अमित त्रिपाठी, डा. अनिल मिश्र, डॉ अमरनाथ, डॉ साजेदा सिद्दीकी, उत्कर्ष गुप्ता एवं महविद्यालय के समस्त स्टाफ द्वारा सहयोग प्रदान किया गया।

सामूहिक विवाह में योजना में 12 जोड़े एक–दूजे के हुए



संवाददाता—अम्बेडकरनगर। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत शनिवार को नगर पालिका परिषद अकबरपुर के डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी बारात घर, गदायां में सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में नगर पालिका परिषद अकबरपुर के कुल 12 जोड़ों का विवाह पूरे रीति–रिवाज एवं पारंपरिक विधि–विधान के साथ संपन्न कराया गया।जिला समाज कल्याण अधिकारी त्रिनेत्र कुमार सिंह ने बताया कि कार्यक्रम में सभी 12 जोड़ों का विवाह सम्पन्न हुआ। सामूहिक विवाह कार्यक्रम अध्यक्ष/प्रशासक जिला पंचायत श्यामसुंदर वर्मा की उपस्थिति में संपन्न कराया गया। इस अवसर पर नवविवाहित जोड़ों को वैवाहिक जीवन में प्रवेश करने पर अतिथियों ने उनके सुखद एवं मंगलमय दांपत्य जीवन के लिए शुभकामनाएं दी।

मां की डांट से नाराज होकर निकलीं दो बच्चियां, बरामद

संवाददाता—गोरखपुर। क्षेत्र के बरगदवा गांव से शनिवार सुबह मां की डांट से नाराज होकर घर से निकलीं दो बच्चियों को पुलिस ने करीब 12 घंटे बाद महराजगंज जिले के लेहड़ा देवी मंदिर से सकुशल बरामद कर लिया। पुलिस ने दोनों को परिजनों के सुपुर्द कर दिया। जानकारी के मुताबिक, महराजगंज जिले के ठूठीबारी निवासी बंशीधर मद्धेशिया परिवार के साथ बरगदवा गांव में किराये का कमरा लेकर रहते हैं। शनिवार सुबह करीब नौ बजे उनकी बेटी सोनाक्षी (12) और सोनू (6) मां की डांट से नाराज होकर घर से निकल गईं। काफी तलाश के बाद भी दोनों का पता नहीं चला तो परिजनों ने दोपहर करीब दो बजे चिलुआताल थाने में तहरीर दी।

इसके बाद थानाध्यक्ष राणा प्रताप सिंह के निर्देश पर बरगदवा चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक अजय वर्मा ने टीम के साथ सीसीटीवी फुटेज की मदद से तलाश शुरू की। करीब 12 घंटे बाद दोनों बच्चियां लेहड़ा देवी मंदिर के पास मिलीं। पुलिस ने उन्हें सकुशल परिजनों को सौंप दिया।

खुनियांव बीआरसी में शिक्षकों को बालिका सशक्तिकरण का प्रशिक्षण

संवाददाता—सिद्धार्थनगर। खुनियांव ब्लॉक संसाधन केंद्र (बीआरसी) में शनिवार को मीना मंच एवं पावर एंजेल के तहत दो दिवसीय प्रशिक्षण पूरा हुआ। इसमें शिक्षकों को बालक–बालिकाओं की समानता, शिक्षा, नेतृत्व, आत्मविश्वास और सामाजिक भागीदारी के बारे में जानकारी दी गई। प्रशिक्षण में संदर्भदाता मुदिता सिंह और आशुतोष त्रिपाठी ने शिक्षकों का मार्गदर्शन किया। मुदिता सिंह ने रूढ़िवादी सामाजिक धारणाओं पर बात की। उन्होंने बालिकाओं को अपनी बात खुलकर रखने, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने और हर क्षेत्र में भागीदारी करने के लिए प्रेरित किया। आशुतोष त्रिपाठी ने बालक–बालिकाओं में नेतृत्व क्षमता विकसित करने, आत्मशक्ति, आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने स्कूलों में बच्चों को सकारात्मक माहौल देने पर जोर दिया। यूनाइटेड टीचर्स एसोसिएशन (यूटा) के जिलाध्यक्ष अभय कुमार पांडेय ने कहा कि बालक–बालिकाओं को शिक्षा के साथ आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनाना जरूरी है। केंद्र और प्रदेश सरकार बालिकाओं की शिक्षा, सुरक्षा और स्वावलंबन के लिए योजनाएं चला रही हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षकों की जिम्मेदारी है कि वे समाज को जागरूक करें और पात्र बालिकाओं तक योजनाओं का लाभ पहुंचाएं।

प्रशिक्षण में जेंडर और लैंगिक समानता समेत सामाजिक मुद्दों पर चर्चा हुई। शिक्षकों को स्कूलों में समानता, सम्मान, सुरक्षा और सकारात्मक माहौल बनाने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम में शशिप्रभा मिश्रा, डॉली शर्मा, ममता चौधरी, जोहरा फातिमा मलिक, प्रिंशु पटेल, नीलिमा पांडेय, सतीश कुमार, अरविंद श्रीवास्तव, अजय त्रिपाठी, धर्मपाल, संदीप कुमार मौर्य, बदुजमा, मयंक श्रीवास्तव, आशुतोष पांडेय और दिनेश कुमार समेत कई शिक्षक–शिक्षिकाएं मौजूद रहे।

दैनिक भारतीय बस्ती
संस्थापक सम्पादक स्व. दिनेश चन्द्र पाण्डेय
स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक प्रदीप चन्द्र पाण्डेय द्वारा दर्पण प्रिन्टिंग प्रेस वि0. नया हाल 1–4 A लोहिया काम्पलेक्स जिला पंचायत भवन गांधीनगर बस्ती (उ.प्र.) से मुद्रित एवं प्रकाशित।

प्रबन्ध सम्पादक–**दिनेश सिंह**
संयुक्त सम्पादक–**प्रदीप चन्द्र पाण्डेय**
अयोध्या–फैजाबाद कार्यालय–
चतुर्भुमंदिर परिसर लक्ष्मण घाट
अयोध्या–फैजाबाद
लखनऊ कार्यालय–
आशियाना चौराहा, एल.डी.ए. कालोनी, सेक्टर एच, कानपुर रोड लखनऊ।
गोरखपुर कार्यालय–
इलाहीबाग गोरखपुर।
मो0 9336715406, 8400925463
ई.मेल bhartiyabasti@gmail.com
dainikbhartiyabasti@gmail.com